www.railsamacharbureau.com

सम्पूर्ण भारतीय रेल जगत का प्रथम पाक्षिक, प्रयागराज से प्रकाशित

रेल समाचार ब्यूरो

सन् 1990 से रेल सेवा में समर्पित

"भारतीय रेल सबसे बड़ा परिवहन नेटवर्क है। यह हर वर्ग के लोगों की जरूरत पूरी करती है।"

"रेलवे सुरक्षित और किफायती यात्रा प्रदान करती है। यह आम जनता की पहली पसंद है।"

वर्ष-36 अंक:07 रेल समाचार ब्यूरो प्रयागराज 01-16 अप्रैल 2026 पृष्ठ 12, मूल्य:20 रु. मात्र. डाक खर्च (रंगीन सहित)

भारतीय रेल ने संचार और कवच प्रणाली के उन्नयन के लिए 1,236 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी

मध्य रेलवे के पाँचों मंडलों में 623.63 करोड़ रुपये की लागत से ड्यूल फाइबर संचार नेटवर्क स्थापित किया जाएगा

गुजरात के राजकोट और भावनगर मंडलों में 302.26 करोड़ रुपये की लागत से फाइबर संचार नेटवर्क पूरा किया जाएगा

तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के उच्च-यातायात वाले 548 किमी मार्गों पर 310.18 करोड़ रुपये की लागत से कवच 4.0 टक्कर-रोधी प्रणाली लागू की जाएगी

सूत्र/पीआईबी- भारतीय रेल ने लगभग 1,236 करोड़ रुपये की लागत वाली कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनका उद्देश्य संचार व्यवस्था को अद्यतन करना और विभिन्न जोन में कवच स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। इन मंजूरियों में तीन अलग-अलग प्रस्ताव शामिल हैं। इनमें से दो प्रस्ताव मध्य और पश्चिम रेलवे में ऑप्टिकल फाइबर और ग्राउंड वायर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से संबंधित हैं, जबकि एक प्रस्ताव दक्षिण रेलवे के उच्च उपयोग वाले मार्गों पर कवच प्रणाली के कार्यान्वयन से जुड़ा है।

मध्य रेलवे को उन्नत फाइबर नेटवर्क मिलेगा: 623.63 करोड़ रुपये

मध्य रेलवे के पूरे नेटवर्क में मजबूत, मॉड्यूल-पाथ संचार व्यवस्था विकसित करने के लिए दो पूरक कार्यों को मंजूरी दी गई है, जो इसके पाँचों मंडलों - सोलापुर, नागपुर, पुणे, भुसावल और मुंबई - को कवर करेंगे।

पहले चरण में, ओपीजीडब्ल्यू (96 फाइबर) नामक एक विशेष प्रकार की कंपोजिट ओवरहेड वायर को मौजूदा 25 केवी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन लाइनों के साथ 2,250.68 आरकेएम पर स्थापित किया जाएगा। इसके तहत सोलापुर, नागपुर, पुणे और भुसावल मंडलों को कवर किया जाएगा। यह वायर एक साथ दो काम करती है: यह ट्रैक्शन सिस्टम के लिए अर्थ प्रोटेक्शन वायर का काम करती है और साथ ही संचार के लिए ऑप्टिकल फाइबर भी प्रदान करती है। चूंकि यह मौजूदा ट्रैक्शन टावरों पर ही लगाई जाएगी, इसलिए किसी नए सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं होगी। इसकी लागत 238.9363 करोड़ रुपये है।

दूसरे चरण में, अंडरग्राउंड ऑप्टिकल फाइबर केबल (2X48 फाइबर) को ट्रैक के एक तरफ 2,673.21 आरकेएम तक बिछाया जाएगा। इसके तहत सोलापुर, पुणे, नागपुर, भुसावल और मुंबई - पाँचों मंडलों को कवर किया जाएगा। दूसरी तरफ लगाए गए ओपीजीडब्ल्यू के साथ मिलकर यह प्रत्येक रूट पर दो स्वतंत्र फाइबर मार्ग तैयार करेगा, जिससे किसी एक मार्ग के फेल होने पर भी संचार नेटवर्क लगातार चालू रहेगा। इसकी लागत 384.6887 करोड़ रुपये है। अतिरिक्त फाइबर क्षमता को 'डार्क फाइबर' के रूप में लीज पर भी दिया जाएगा, जिससे भारतीय रेल को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

दक्षिण रेलवे पर कवच सुरक्षा प्रणाली का 548 किमी तक विस्तार: 310.18 करोड़ रुपये

कवच भारतीय रेल की स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, जो दो ट्रेनों के आमने-सामने आने या किसी ट्रेन द्वारा सिग्नल को खतरे की स्थिति में पार करने पर स्वत: ब्रेक लगाकर टक्कर को रोकती है। इस मंजूरी के तहत इसे तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के उच्च-यातायात वाले मार्गों पर लागू किया जाएगा। इस स्वीकृति के अंतर्गत, दक्षिण रेलवे के दो खंडों पर कवच संस्करण 4.0 को तैनात किया जाएगा।

जोलारपेट्टई-इरोड (180 आरकेएम, सलेम मंडल) और चेन्नई बीच - तांबरम चेंगलपट्टू (60 किमी, चेन्नई मंडल) खंडों पर, नवीन ऑप्टिकल फाइबर केबलिंग के साथ। लागत: 158.74 करोड़ रुपये ।

शोरनूर-मैंगलोर (308 किमी, पालक्काड मंडल) - नए 4X48 फाइबर ओएफसी केबलिंग के साथ। लागत: 151.44 करोड़ रुपये । ये कार्य दक्षिण रेलवे की 2,950 करोड़ रुपये की सब-अम्ब्रेला परियोजना का हिस्सा हैं।

पश्चिम रेलवे राजकोट और भावनगर मंडलों के लिए फाइबर बैकबोन पूरा करेगा: 302.2589 करोड़ रुपये

गुजरात में पश्चिम रेलवे के दो मंडलों के शेष हिस्सों पर ऑप्टिकल फाइबर केबल (2X48 फाइबर, ट्रैक के दोनों ओर) बिछाए जाएंगे - राजकोट मंडल में 1,064 किमी और भावनगर मंडल में 589 किमी, कुल मिलाकर 1,653 किमी। इससे इन मंडलों के फाइबर संचार नेटवर्क की अंतिम कमी भी पूरी हो जाएगी।

कवच और एलटीई आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणालियों के विश्वसनीय संचालन के लिए एक मजबूत फाइबर बैकबोन अत्यंत आवश्यक है। इस नेटवर्क के पूरा होने से पश्चिम रेलवे में कवच के कार्यान्वयन को बिना किसी देरी के आगे बढ़ाया जा सकेगा। ये सभी कार्य पश्चिम रेलवे की 2,800 करोड़ रुपये की सब-अम्ब्रेला परियोजना का हिस्सा हैं।

यह परियोजनाएं भारतीय रेल की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं, जिसके तहत उन्नत संचार प्रणालियों और सुरक्षा तकनीकों के एकीकरण के माध्यम से बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। ट्रैक्शन से जुड़ी संचार प्रणालियों को मजबूत करना और ओएफसी नेटवर्क का विस्तार, कवच प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे संचालन क्षमता में सुधार होगा, सुरक्षा बढ़ेगी और देशभर में भविष्य के लिए तैयार रेलवे संचालन को सक्षम बनाया जा सकेगा।

गुजरात में कोसंबा रेल-ओवर-रेल फ्लाईओवर और बिहार में भागलपुर बाईपास को मंजूरी

रेल मंत्रालय ने पश्चिमी और पूर्वी रेलवे में दो महत्वपूर्ण रेल अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनका उद्देश्य कनेक्टिविटी बढ़ाना, भीड़भाड़ कम करना और परिचालन क्षमता में सुधार करना है। इन परियोजनाओं में गुजरात के कोसंबा-उमरापाड़ा गेज रूपांतरण खंड से कनेक्टिविटी के लिए कोसंबा में रेल-ओवर-रेल (आरओआर) फ्लाईओवर का निर्माण और बिहार के भागलपुर में एक नए रेल बाईपास का विकास शामिल है। दोनों परियोजनाओं की कुल स्वीकृत लागत 647.58 करोड़ रूपये है।

पश्चिमी रेलवे के कोसांबा-उमरापाड़ा जीसी खंड पर 9.20 किमी रेल-ओवर-रेल फ्लाईओवर की स्वीकृति - भारतीय रेलवे ने कोसांबा-उमरापाड़ा गेज रूपांतरण (जीसी) खंड को निर्बाध रूप से जोड़ने के लिए 9.20 किमी रेल-ओवर-रेल फ्लाईओवर के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की अनुमानित कुल लागत 344.38 करोड़ रूपये है। कोसांबा-उमरापाड़ा खंड मुंबई-वडोदरा मुख्य लाइन के पूर्वी हिस्से में स्थित है और इसका गेज रूपांतरण कार्य वर्तमान में चल रहा है।

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अलाइनमेंट की मौजूदगी के कारण, गेज परिवर्तित लाइन को मुख्य लाइन से सीधे जोड़ने के लिए सतही क्रॉसिंग संभव नहीं है। स्वीकृत रेल-ओवर-रेल फ्लाईओवर से सतही क्रॉसिंग की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी और गेज रूपांतरण खंड का मुंबई-वडोदरा मुख्य लाइन के साथ निर्बाध एकीकरण संभव हो सकेगा। इससे इन महत्वपूर्ण मार्गों पर रेलगाड़ियों का निर्बाध और सुरक्षित संचालन सुनिश्चित होगा और गेज रूपांतरण परियोजना के सभी लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

पूर्वी रेलवे द्वारा भागलपुर 13.38 किमी बाईपास की स्वीकृति - मंत्रालय ने पूर्वी रेलवे में 13.38 किमी लंबे भागलपुर बाईपास के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है, जिसकी अनुमानित लागत 303.20 करोड़ रुपये है। यह बाईपास बरहट-भागलपुर खंड पर स्थित गोनुधाम हॉल्ट को भागलपुर-साहिबगंज खंड पर स्थित सबौर से जोड़ेगा, जिससे भागलपुर जंक्शन पर यातायात की भीड़ कम होगी।

वर्तमान में, बरहट-भागलपुर खंड 125 प्रतिशत से अधिक क्षमता उपयोग पर चल रहा है, जिससे भारी भीड़भाड़ हो रही है। बरहट-भागलपुर और भागलपुर-साहिबगंज खंडों के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों को भागलपुर में इंजन बदलना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप देरी और परिचालन में अक्षमताएं उत्पन्न होती हैं। स्वीकृत बाईपास से परिचालन सुगमता और समयबद्धता में उल्लेखनीय सुधार होगा। इन बुनियादी ढांचागत कार्यों से गुजरात और बिहार में रेल संपर्क मजबूत होगा, सुरक्षा बढ़ेगी, भीड़ कम होगी और रेल परिचालन की क्षमता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय देश की बढ़ती यात्री और माल ढुलाई मांगों को पूरा करने के लिए क्षमता विस्तार और नेटवर्क में भीड़ कम करने को प्राथमिकता देता रहेगा।

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत दिल्ली के 13 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की प्रगति

नई दिल्ली, सफदरजंग, बिजवासन और दिल्ली कैंट स्टेशनों पर संरचनात्मक कार्य पूरा किया गया

सूत्र/पीआईबी - रेल मंत्रालय द्वारा देशभर के रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से अमृत भारत स्टेशन योजना लागू की गई है, जिसके अंतर्गत अब तक कुल 1338 स्टेशनों को पुनर्विकास के लिए चिन्हित किया गया है। इस योजना में दिल्ली के 13 रेलवे स्टेशन शामिल हैं, जहां विभिन्न स्तरों पर विकास कार्य किए जा रहे हैं।

दिल्ली में चयनित प्रमुख स्टेशनों में नई दिल्ली, सफदरजंग, बिजवासन और दिल्ली कैंट स्टेशन पर संरचनात्मक कार्य पूरा किया जा चुका है, जो परियोजना की प्रगति को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, योजना के तहत जिन 13 स्टेशनों को शामिल किया गया है, उनके नाम हैं: आदर्शनगर दिल्ली, आनंद विहार, बिजवासन, दिल्ली, दिल्ली कैंट, दिल्ली सराय रोहिल्ला, दिल्ली शहादरा, हजरत निजामुद्दीन, नरेला, नई दिल्ली, सब्जी मंडी, सफदरजंग और तिलक ब्रिज।

रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में बताया कि इस योजना का उद्देश्य स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करना, यात्री अनुभव को बेहतर बनाना और रेलवे अवसंरचना को मजबूत करना है। दिल्ली के इन स्टेशनों का पुनर्विकास राजधानी क्षेत्र में रेल सेवाओं की गुणवत्ता और क्षमता दोनों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

दिल्ली में स्थित कुछ स्टेशनों पर विकास के लिए गतिविधियां -

सफदरजंग: सिग्नल और टेलीकॉम बिल्डिंग के निर्माण का काम पूरा हो चुका है और इसे चालू कर दिया गया है। स्टेशन भवन का काम पूरा हो चुका है और फिनिशिंग का काम शुरू हो चुका है। परिचालन भवन का संरचनात्मक कार्य पूरा हो गया है। एयर कॉनकोर्स की नींव और स्तंभ निर्माण पूरा हो चुका है और गर्डर्स की लॉन्चिंग शुरू कर दी गई है। डिपार्चर प्लाजा कैनोपी के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। प्लेटफार्म शेल्टर की व्यवस्था, सर्कुलेशन और एप्रोच रोड में सुधार का काम शुरू कर दिया गया है।

बिजवासन: स्टेशन भवन और एयर कॉनकोर्स का संरचनात्मक कार्य पूरा हो चुका है और परिष्करण कार्य शुरू कर दिया गया है। प्लेटफार्म शेल्टर का काम शुरू कर दिया गया है। विद्युत सब-स्टेशन का संरचनात्मक कार्य पूरा कर लिया गया है और खाई बिछाने का काम शुरू कर दिया गया है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और सबवे का संरचनात्मक कार्य पूरा हो चुका है और परिष्करण कार्य शुरू कर दिया गया है।

दिल्ली कैंट: ईस्ट साइड स्टेशन भवन (भाग 1) का संरचनात्मक कार्य और आवासीय क्वार्टरों का संरचनात्मक कार्य पूरा हो चुका है। ईस्ट साइड स्टेशन बिल्डिंग (भाग 2), एलिवेटेड रोड, आगमन और प्रस्थान कॉनकोर्स, रेलवे क्वार्टर का फिनिशिंग कार्य, बाहरी विकास का निष्पादन, प्लेटफॉर्म, ओवरहेड टैंक का नवीनीकरण और ईस्ट साइड स्टेशन बिल्डिंग (भाग 1) की फिनिशिंग के लिए संरचनात्मक कार्य पूरे कर किए गए हैं।

नरेला स्टेशन: प्लेटफार्म शेल्टर, प्लेटफार्म सरफेसिंग, आधुनिक शौचालय, सर्कुलेटिंग एरिया, पार्किंग और दिव्यांगजन सुविधाओं का काम शुरू कर दिया गया है।

सब्जी मंडी स्टेशन: नए स्टेशन भवन, प्लेटफार्म शेल्टर, प्लेटफार्म सरफेसिंग, आधुनिक शौचालय, सर्कुलेटिंग एरिया, पार्किंग, दिव्यांगजन सुविधाएं, लिफ्ट और 12 मीटर फुट ओवर ब्रिज का काम शुरू कर दिया गया है।

तिलक ब्रिज स्टेशन: नए स्टेशन भवन, प्लेटफार्म शेल्टर, प्लेटफार्म सरफेसिंग, आधुनिक शौचालय, सर्कुलेटिंग एरिया, पार्किंग, दिव्यांगजन सुविधा और लिफ्ट का काम शुरू हो गया है।

नई दिल्ली: अजमेरी गेट साइड पर होल्डिंग एरिया के प्रावधान का काम पूरा हो चुका है और पहाड़गंज साइड में पार्ट स्टेशन बिल्डिंग को गिराने के लिए कार्यालयों और यात्री सुविधाओं को स्थानान्तरित करने का काम भी पूरा हो चुका है। पहाड़गंज साइड में डबल बेसमेंट के निर्माण, एलिवेटेड रोड की नींव का काम शुरू कर दिया गया है।

मास्टर प्लानिंग के लिए बनाए गए स्टेशन विभिन्न चरणों में हैं। मास्टर प्लानिंग एक पुनराव त्तीय प्रक्रिया है जिसमें अनुकूलन की आवश्यकता होती है और इस स्तर पर ऐसे अनुकूलन के लिए समय सीमा का संकेत नहीं दिया जा सकता है।

इस योजना में टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल समाधान, आवश्यकता के अनुसार गिट्टी रहित पटरियों का प्रावधान, चरणबद्ध और व्यवहार्यता और लंबी अवधि में स्टेशन पर सिटी सेंटर के निर्माण की भी परिकल्पना की गई है।

तुगलकाबाद स्टेशन पर स्पर्श पथ, मानक साइनेज, पार्किंग, शौचालय रैंप प्रदान करके दिव्यांगजन सुविधाओं के प्रावधान के कार्यों को हाल ही में मंजूरी दी गई है। रेलवे परिसर के भीतर सड़कों का रखरखाव समय-समय पर किया जाता है। हालाँकि, रेलवे सीमा के बाहर सड़कों का रखरखाव राज्य सरकार या स्थानीय अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

इसके अलावा, भारतीय रेलवे पर स्टेशनों का विकास/पुनर्विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण एक सतत और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और इस संबंध में कार्य आवश्यकता के अनुसार किए जाते हैं, जो प्राथमिकता और धन की उपलब्धता के अधीन हैं। किसी स्टेशन का विकास/पुनर्विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण स्टेशन/स्थिति/यातायात संचालन आदि की श्रेणी के आधार पर किया जाता है।

इसके अलावा, रेलवे स्टेशनों का विकास/पुनर्विकास/उन्नयन प्रकृति में जटिल है जिसमें यात्रियों और रेलगाडियों की सुरक्षा शामिल है और इसके लिए विभिन्न वैधानिक मंजूरी की आवश्यकता होती है जैसे कि अग्नि मंजूरी, विरासत, पेड़ काटने, हवाई अड्डे की मंजूरी आदि भूरे क्षेत्र से संबंधित चुनौतियों के कारण प्रगति भी प्रभावित होती है जैसे उपयोगिताओं का स्थानांतरण, (पानी/सीवेज लाइनें, ऑप्टिकल फाइबर केबल, गैस पाइप लाइन, बिजली/सिग्नल केबल आदि शामिल हैं) उल्लंघन, यात्रियों की आवाजाही में बाधा डाले बिना रेलगाडियों का संचालन, उच्च वोल्टेज बिजली लाइनों के निकट किए गए कार्यों के कारण गति प्रतिबंध आदि कारक कार्य पूरा होने के समय को प्रभावित करते हैं। इसलिए, इस स्तर पर कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

प्रत्येक स्टेशन पर आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मास्टर प्लानिंग में शामिल हैं:-

- स्टेशन और परिसंचारी क्षेत्रों तक पहुंच में सुधार
- शहर के दोनों किनारों के साथ स्टेशन का एकीकरण
- स्टेशन भवन का सुधार
- प्रतीक्षालय कक्ष, शौचालय, बैठने की व्यवस्था, वाटर बूथ में सुधार
- यात्री यातायात के अनुरूप व्यापक फुट ओवर ब्रिज/एयर कॉनकोर्स का प्रावधान
- लिफ्ट/एस्केलेटर/रैंप का प्रावधान
- प्लेटफॉर्म की सतह और प्लेटफॉर्म पर कवर का सुधार/प्रावधान
- 'वन स्टेशन वन प्रोडक्ट' जैसी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क का प्रावधान
- पार्किंग क्षेत्र, मल्टीमॉडल एकीकरण
- दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं
- बेहतर यात्री सूचना प्रणाली
- कार्यकारी लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए नामांकित स्थान, भूनिर्माण आदि का प्रावधान।

भारतीय रेलवे में अनधिकृत बिक्री को समाप्त करने और रेल यात्रियों के लिए प्रमाणित खानपान सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए क्यूआर कोड-सक्षम पहचान पत्र और डिजिटल रूप से ट्रेस करने योग्य खाद्य पैकेटों का उपयोग किया जाएगा

आधुनिक रसोई, अनिवार्य एफएसएसएआई प्रमाणन, सीसीटीवी निगरानी, औचक निरीक्षण और तृतीय-पक्ष ऑडिट के माध्यम से यात्रियों को स्वच्छ और उच्च गुणवत्तापूर्ण भोजन

सूत्र/रे.स.ब्यू - रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी कि भारतीय रेलवे के यात्रियों के बीच अनधिकृत रूप से सामान बेचना और फेरी लगाना प्रतिबंधित है। यह रेल अधिनियम, 1989 की धारा 144 के तहत दंडनीय अपराध है। ट्रेनों में अनधिकृत विक्रेताओं के प्रवेश को रोकने के लिए नामित अधिकारियों और रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ) द्वारा नियमित निरीक्षण किए जाते हैं। रेलवे परिसर में अनधिंत बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए रेलवे और आईआरसीटीसी के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर विशेष अभियान भी चलाए जाते हैं।

ट्रेनों में अधिकृत विक्रेताओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए, ट्रेन में खानपान सेवाओं के प्रबंधन हेतु तैनात प्रत्येक विक्रेता/सहायक/कर्मचारी के नाम पर क्यूआर कोड युक्त पहचान पत्र जारी करना अनिवार्य कर दिया गया है। यह क्यूआर कोड विक्रेता का नाम, आधार नंबर, मेडिकल फिटनेस, पुलिस सत्यापन का विवरण आदि प्रदर्शित करके कर्मचारी की प्रामाणिकता को सुनिश्चित करता है। अनधिकृत बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए अन्य उपायों में खाद्य पैकेटों पर क्यूआर कोड लगाना शामिल है, जिसमें रसोई का नाम और निर्माण की तिथि आदि प्रदर्शित होती है।

गुणवत्ता, स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

- निर्धारित बेस किचन से भोजन की आपूर्ति।
- चिन्हित स्थानों पर आधुनिक बेस किचन की स्थापना।
- भोजन तैयार करने की प्रक्रिया की बेहतर निगरानी के लिए बेस किचन में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।
- खाना पकाने के तेल, आटा, चावल, दालें, मसाला सामग्री, पनीर, डेयरी उत्पाद आदि जैसे लोकप्रिय और ब्रांडेड कच्चे माल का चयन और खाद्य उत्पादन के लिए उनका उपयोग।
- खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता प्रणालियों की निगरानी के लिए मुख्य रसोईघरों में खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षकों की तैनाती।
- ट्रेनों में आईआरसीटीसी के पर्यवेक्षकों की तैनाती।
- बेस किचन और पैंट्री कारों में नियमित रूप से गहन सफाई और समय-समय पर कीट नियंत्रण।
- खाद्य सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक खानपान इकाई के नामित खाद्य सुरक्षा अधिकारियों से भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) का प्रमाणन अनिवार्य कर दिया गया है।
- ट्रेनों में भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण और निगरानी प्रणाली के हिस्से के रूप में नियमित रूप से भोजन के नमूने लेना।
- पेंट्री कारों और बेस किचन में भोजन की स्वच्छता और गुणवत्ता की जांच के लिए तृतीय-पक्ष ऑडिट किया जाता है। ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण भी आयोजित किया जाता है।
- खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा औचक निरीक्षण।
- आईआरसीटीसी द्वारा खानपान कर्मचारियों के कौशल को बढ़ाने के लिए नियमित प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है, जिसमें ग्राहक सेवा क्षेत्रों जैसे संवाद, विनम्र व्यवहार, सेवा मानक, व्यक्तिगत साज-सज्जा और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

रेल मदद ने हेल्पलाइन 139, वेब, ऐप और एसएमएस के साथ यात्री सुविधाओं को बढ़ाया, एकीकृत शिकायत निवारण और फीडबैक की भी सुविधा बढ़ाई और उसके समाधान की व्यवस्था भी है

सूत्र/रे.स.ब्यू -रेल मदद भारतीय रेलवे की शिकायत निवारण प्रणाली है, जो यात्रियों को शिकायत, सहायता और पूछताछ के लिए एक एकीकृत प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। रेलमदद के माध्यम से यात्री हेल्पलाइन नंबर 139, रेलमदद वेब, ऐप और एसएमएस जैसे कई माध्यमों से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। रेलमदद यात्रियों को उनकी शिकायत के समाधान पर फीडबैक देने की सुविधा भी प्रदान करता है।

रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी कि भारतीय रेलवे अपनी ट्रेनों में हर साल लगभग 58 करोड़ भोजन परोसता है, जिनमें शिकायतों की औसत दर केवल लगभग 0.0008% है, जिसमें अधिक वसूली (ओवरचार्जिंग) से संबंधित शिकायतें भी शामिल हैं। इन शिकायतों की जांच के बाद पिछले तीन वर्षों में 2.6 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। वर्ष 2025 के दौरान पैंट्री कार स्टाफ द्वारा रेल यात्रियों पर हमले की 3 घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं। संबंधित सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा पैंट्री कार स्टाफ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। भारतीय रेलवे लगातार यह प्रयास कर रहा है कि यात्रियों को निर्धारित दरों पर खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जाएं। इसे सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर आवश्यक कदम उठाए जाते हैं।

ट्रेनों में ओवरचार्जिंग रोकने के लिए रेलवे द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- यात्रियों को मेन्यू और दरों की जानकारी देने के लिए लिंक सहित एसएमएस भेजा जाता है।
- बिलिंग और कैशलेस भुगतान के लिए पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीनों की स्थापना।
- बिलिंग को बढ़ावा देने और ओवरचार्जिंग रोकने के लिए जागरूकता अभियान।
- पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर (पीडीडब्ल्यू) बाल्टी और चाय/कॉफी कंटेनरों पर रेट स्टिकर।
- मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में ई-पैंट्री सेवा शुरू, जिससे यात्री ऑनलाइन भोजन बुक कर सकें।
- कैटरिंग स्टाफ के लिए क्यूआर कोड आधारित पहचान पत्र लागू।
- कैटरिंग आइटम और पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर की दरों की जानकारी के लिए पंपलेट वितरण।
- ओवरचार्जिंग और बिलिंग की जांच के लिए विशेष निरीक्षण अभियान।
- ओवरचार्जिंग पाए जाने पर उचित जुर्माना लगाया जाता है।
- ट्रेनों में ऐसी कोई घटना रिपोर्ट होने पर सेवा प्रदाताओं के खिलाफ तुरंत और उचित दंडात्मक कार्रवाई की जाती है।

ट्रेनों में क्षेत्रीय व्यंजन- रेल मंत्रालय ने वाणिज्यिक परिपत्र संख्या 25/2022 के माध्यम से आईआरसीटीसी को ट्रेनों के मेन्यू को क्षेत्रीय व्यंजनों, मौसमी पकवानों और हेल्दी फूड विकल्पों (जिसमें मिलेट आधारित उत्पाद शामिल हैं) के अनुसार अनुकूलित करने की अनुमति दी है। उपरोक्त निर्देश के अनुसार आईआरसीटीसी ने यात्रियों के फीडबैक के आधार पर मेन्यू तैयार किया है।इन क्षेत्रीय/स्थानीय व्यंजनों को शामिल करने से यात्रियों को प्रामाणिक स्थानीय स्वादों का आनंद लेने और स्थानीय संस्कृति से जुड़ने का अवसर मिलता है।

केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों के साथ यात्री सुविधाओं और सुरक्षा की समीक्षा की, समयबद्ध तरीके से पहुंच नियंत्रण और एआई-आधारित सुधार लागू करने के निर्देश दिए

सूत्र/पीआईबी - रेल, सूचना और प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में रेल भवन में वरिष्ठ रेल अधिकारियों के साथ एक व्यापक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक का उद्देश्य स्टेशन पहुंच, यात्री सुविधाओं के उन्नयन और यात्री अनुभव को बेहतर बनाने के लिए किए गए अन्य सुरक्षा संबंधी उपायों की प्रगति का आकलन करना था। बैठक में प्रवेश नियंत्रण, भीड़ प्रबंधन, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी और स्टेशन परिसर के भीतर सुगम आवागमन जैसे उपायों पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये सुधार सर्वप्रथम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लागू किए जाएंगे और प्राप्त अनुभवों के आधार पर इन्हें अन्य स्टेशनों पर भी क्रियान्वित किया जाएगा।

एआई-संचालित कैमरा नेटवर्क चौबीसों घंटे निगरानी सुनिश्चित करेगा

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर व्यापक एआई-संचालित निगरानी प्रणाली को कैमरों के माध्यम से तैनात किया जाएगा, जो प्लेटफॉर्म, कॉनकोर्स, प्रवेश-निकास बिंदुओं और अनधिकृत प्रवेश की संभावना वाले क्षेत्रों सहित स्टेशन परिसर के हर कोने को कवर करेगी।

एक एक्सेप्शन इवेंट डिस्प्ले आधारित नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा, जहां लाइव कैमरा फीड की एआई प्रोसेसिंग द्वारा निगरानी कर्मचारियों को असामान्य या असुरक्षित घटनाओं के बारे में वास्तविक समय में सूचित किया जाएगा। श्री वैष्णव ने कैमरों को सिस्टम की ''आंखें'' और एआई को ''मस्तिष्क'' बताया और इस बात पर बल दिया कि अधिकतम निगरानी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए सभी कैमरा कवरेज जोन में पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) को अतिरिक्त रूप से तैनात किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल टिकट धारक यात्री ही स्टेशन परिसर में प्रवेश कर सकें और मैनुअल चेकिंग के बजाय निगरानी-आधारित मॉनिटरिंग को अपनाया जाएगा।

सभी स्टेशन कर्मचारियों के लिए कलर-कोडेड वर्दी और पहचान पत्र

विशाल कार्यबल में एकरूपता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, स्टेशन पर कार्यरत सभी कर्मियों के लिए रंग-आधारित पहचान प्रणाली लागू की गई है। रेलवे कर्मचारी फ्लोरोसेंट जैकेट पहनेंगे, जबकि विक्रेता, स्टेशन सहायक, संविदा कर्मचारी और आईआरसीटीसी कर्मियों सहित गैर-कर्मचारी भी किसी अन्य रंग की जैकेट पहनेंगे। यह कदम स्टेशन परिसर में मौजूद यात्रियों, कर्मचारियों और अन्य गैर-कर्मचारियों जैसे कुली, विक्रेताओं के कर्मचारी, भोजन, सफाई, पार्सल और रखरखाव कर्मियों की त्वरित पहचान सुनिश्चित करने के लिए उठाया जा रहा है, जिनसे सुरक्षा अधिकारी और टिकट जांच कर्मचारी अपने कर्तव्यों का पालन करते समय संपर्क में रहते हैं।

सभी कर्मचारियों और गैर-कर्मचारियों को पहचान पत्र जारी किए जाएंगे, जिनमें पहचान के लिए आवश्यक सभी विवरण शामिल होंगे। इस एकसमान पहचान प्रणाली को धीरे-धीरे उत्तरी क्षेत्र के सभी स्टेशनों पर लागू किया जाएगा, जिसमें नई दिल्ली स्टेशन को मॉडल के रूप में रखा जाएगा और बाद में इसे देश के अन्य हिस्सों में भी क्रियान्वित किया जाएगा।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर क्यूआर कोड आधारित प्रवेश नियंत्रण प्रणाली का प्रायोगिक परीक्षण किया जाएगा

दिवाली और छठ पर्व के दौरान संभावित भीड़भाड़ से पहले, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में क्यूआर कोड आधारित प्रवेश प्रबंधन प्रणाली शुरू की जा रही है। यह प्रणाली वैध टिकटों के आधार पर प्रवेश को नियंत्रित करेगी, जिससे आरक्षित टिकट धारकों, मासिक सीजन टिकट धारकों और अनारक्षित यात्रियों को बेहतर ढंग से अलग किया जा सकेगा।

निर्बाध अंतिम-मील कनेक्टिविटी के लिए रेलवन ऐप को भारत टैक्सी के साथ एकीकृत किया जाएगा

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आने-जाने वाले यात्रियों के यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने के लिए, रेलवन ऐप को भारत टैक्सी के साथ एकीकृत किया जा रहा है। रेलटेल के सहयोग से विकसित किए जा रहे इस एकीकरण का उद्देश्य स्टेशन परिसर के बाहर की अव्यवस्था को कम करना, यात्रियों की असुविधा को न्यूनतम करना और एक विश्वसनीय, पारदर्शी अंतिम-मील परिवहन विकल्प प्रदान करना है।

भारत टैक्सी भारत का पहला सहकारी समिति द्वारा संचालित राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म है। यह भारत सरकार के सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने और 'सहकार से समृद्धि' की परिकल्पना के अनुरूप समावेशी, नागरिक-केंद्रित परिवहन समाधानों को बढ़ावा देने के निरंतर प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

भीड़ के सुचारू प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए प्रतीक्षा क्षेत्र

बैठक में 76 रेलवे स्टेशनों पर प्रतीक्षा क्षेत्रों के उन्नयन की स्थिति की भी समीक्षा की गई। अनारक्षित यात्रियों के लिए स्टेशन भवन के बाहर निर्दिष्ट प्रतीक्षा क्षेत्र बनाए जा रहे हैं, जिससे प्लेटफार्मों तक नियंत्रित और चरणबद्ध पहुंच सुनिश्चित होगी और कॉनकोर्स में भीड़भाड़ को रोका जा सकेगा, जो ऐतिहासिक रूप से भीड़भाड़ और सुरक्षा जोखिमों का कारण बनती रही है। सुगम आवागमन के लिए प्रतीक्षा क्षेत्र से होकर यात्रियों के लिए निर्दिष्ट प्रवेश द्वार उपलब्ध होंगे। सभी स्टेशनों पर साइनेज में सुधार के निर्देश दिए गए हैं, जिनमें आरक्षित और अनारक्षित दोनों टिकट धारकों के लिए स्पष्ट और प्रमुखता से दिखाई देने वाले संकेत शामिल हैं। निर्धारित प्रतीक्षा क्षेत्रों में यात्रियों को बेहतर जानकारी उपलब्ध कराने के लिए ट्रेन सूचना सेवाओं को उन्नत किया जाएगा। रेल मंत्रालय द्वारा प्रत्यक्ष निगरानी जारी रहेगी ताकि नेटवर्क के सभी व्यस्त स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा में निरंतर सुधार सुनिश्चित किया जा सके।

ये उपाय भारतीय रेल की देश के सबसे व्यस्त स्टेशनों को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और यात्री-अनुकूल स्थानों में बदलने की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। प्रौद्योगिकी और उन्नत वास्तविक अवसंरचना के संयोजन से, रेलवे का लक्ष्य उन लाखों यात्रियों को स्टेशन में प्रवेश से लेकर अंतिम मील कनेक्टिविटी तक निर्बाध यात्रा अनुभव प्रदान करना है जो प्रतिदिन इसकी सेवाओं पर निर्भर रहते हैं।

प्रयागराज-नैनी के मध्य स्थित ऐतिहासिक यमुना पुल (पुल संख्या 30) के शोर स्पैन का नवीनीकरण कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण

अप लाइन (UP Line): प्रथम शोर स्पैन की लॉन्चिंग 27 मार्च 2026 को की गई।

डाउन लाइन (DN Line): द्वितीय शोर स्पैन की लॉन्चिंग का कार्य 28 मार्च 2026 को संपन्न हुआ।

सूत्र/रे.स.ब्यू - उत्तर मध्य रेलवे द्वारा आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण और रेल संरक्षा की दिशा में एक और मील का पत्थर स्थापित किया गया है। प्रयागराज (PRYJ) और नैनी (NYN) स्टेशनों के मध्य स्थित ऐतिहासिक यमुना पुल (पुल संख्या 30) की अप एवं डाउन (UP & DN) लाइनों के शोर स्पैन (Shore Span) को नए स्टील गर्डर से बदलने का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है।

इस नवीनीकरण से इस व्यस्त रेल खंड पर भविष्य में ट्रेनों का परिचालन और अधिक सुरक्षित एवं तीव्र हो सकेगा।

ऐतिहासिक महत्व और उपयोगिता: यह पुल भारतीय रेल नेटवर्क का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो प्रयागराज को कोलकाता, चेन्नई और मुंबई जैसे देश के प्रमुख महानगरों से जोड़ने वाली एक अहम कड़ी के रूप में कार्य करता है।

वर्ष 1911 में हुए दोहरीकरण के बाद से निरंतर सेवा दे रहे इस पुल की सुरक्षा और निर्बाध परिचालन को सुनिश्चित करने के लिए, रेलवे द्वारा इसके पुराने शोर स्पैन (2X9.15 मीटर) को नए स्टील गर्डर (2X9-1 मीटर) से बदलने की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

यह अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य महाप्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, श्री नरेश पाल सिंह के कुशल मार्गदर्शन एवं मंडल रेल प्रबंधक, श्री रजनीश अग्रवाल के सक्षम नेतृत्व में संपन्न हुआ। इस जटिल इंजीनियरिंग कार्य के निष्पादन में उप मुख्य ब्रिज लाइन इंजीनियर, श्री आई.पी.एस. यादव एवं उनकी समर्पित टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही, मंडल के इंजीनियरिंग विभाग, परिचालन विभाग (Operating) और बिजली विभाग (Electrical) के आपसी समन्वय और सहयोग से इस कार्य को निर्धारित समय सीमा के भीतर सफलतापूर्वक पूरा किया गया।

इस ऐतिहासिक पुल का विवरण निम्नवत है:

मूल उद्घाटन: 15 अगस्त 1865

लाइन का दोहरीकरण (Doubling): वर्ष 1911

री-गर्डरिंग (Regirdering): वर्ष 1929

मथुरा जंक्शन पर चलाया गया मजिस्ट्रेट चौकिंग अभियान।

सूत्र/रे.स.ब्यू - दिनांक 25.03.2026 को मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर रेलवे मजिस्ट्रेट मथुरा श्री सूर्यभान वर्मा द्वारा अनियमित तरीके से यात्रा करने वाले लोगों के विरुद्ध टिकट चौकिंग अभियान चलाया गया।

उक्त जांच अभियान में 39 बिना टिकट यात्रियों पर 14250रु रेल किराए सहित रु 36740/- न्यायालय जुर्माना तथा अनियमित तरीके से यात्रा करने वाले 18 यात्रियों पर 6470 रुपए रेल किराए एवं 16 यात्रियों को अनाधिकृत रूप से रेलवे लाइन पार करने के कारण रुव- 11500/- के अलावा 17 यात्रियों द्वारा निम्न दर्जे का टिकट लेकर आरक्षित कोचों में यात्रा करने के कारण उन पर 6340 रुपए न्यायालय जुर्माना सहित कुल 93 अनाधिकृत यात्री पकड़े गए जिन पर रेल न्यायालय मथुरा द्वारा कुल 54580/- रूपये का जुर्माना लगाया गया। उक्त जांच अभियान में स्टेशन निदेशक मथुरा श्री ए पी श्रीवास्तव सहित श्री हेमंत अग्रवाल CTI/स्टेशन, श्री शैलेश मिश्रा CTI/अभियोजन दल मथुरा सहित बड़ी संख्या में आरपीएफ/जीआरपी बल मौजूद रहा। मंडल में इस प्रकार की जांच लगातार कराई जा रही है, जिससे अनियमित तरीके से यात्रा करने वाले यात्रियों पर रोक लगाई जा सके।

पाठकों से अनुरोध

विगत वर्षों की भाँति आगामी वर्ष के लिए अपनी रेल समाचार ब्यूरो पत्रिका को सुरक्षित करने के लिए वार्षिक सद्स्यता शुल्क शीघ्र भेजने की कृपा करें, जिससे उक्त पत्रिका आपको नियमित भेजी जा सके।

सहयोग राशि:

१. उच्चतम अधिकारी-5000 रु. मात्र
२. उच्च अधिकारी- 3500 रु. मात्र
३. अधीनस्थ अधिकारी-2500 रु. मात्र
४. रेलकर्मी/अन्य सदस्य-1000 रु. मात्र

सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक एवं स्वामी
ज्ञानेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
पंजिकृत कार्यालय
502 पंचशीला भवन त्रिवेनी रोड, नेतानगर, कीडगंज प्रयागराज-211003 से प्रकाशित।
कैंप कार्यालय- अनिल केन (रिर्पोटर) कार्यालय 8439 आर्य नगर पहाड़गंज दिल्ली-55

समस्त प्रकार के कानूनी मामलों का न्यायिक क्षेत्र प्रयागराज होगा

सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक एवं स्वामी
ज्ञानेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
दि. इलाहाबाद ब्लॉक वर्क्स प्रा. लि.
329/255 चक. जीरो रोड इलाहाबाद से मुद्रित एवं 502 पंचशीला भवन त्रिवेनी रोड, नेतानगर, कीडगंज प्रयागराज-211003 से प्रकाशित।
आर.एन. आई नं. 51097-90 पोस्ट ए.डी.-8
मो. 9773946044 / 9793956044
फोन नं. 0532-2418040

रेलवे में मदिरा, तंबाकू और धूम्रपान जैसे कानून की दृष्टि से आपत्तिजनक विज्ञापनों का प्रदर्शन प्रतिबंधित है: रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव

भारतीय रेलवे रेलगाड़ियों (डिब्बों के अंदर और बाहर) के साथ-साथ स्टेशन परिसर में भी विज्ञापनों के लिए नैतिक नीति-आधारित दृष्टिकोण अपनाता है

सूत्र/पीआईबी - रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी कि भारतीय रेलवे ने विज्ञापन और ब्रांडिंग पहलों के माध्यम से गैर-किराया राजस्व अर्जित करने के लिए व्यापक गैर-किराया राजस्व (एनएफआर) नीतियां बनाई हैं। आउट-ऑफ-होम (ओओएच) विज्ञापन नीति के अंतर्गत, स्टेशनों के आवागमन क्षेत्रों में विज्ञापन के अवसर उपलब्ध हैं। रेल डिस्प्ले नेटवर्क (आरडीएन) नीति स्टेशनों और आवागमन क्षेत्रों में स्क्रीन और डिस्प्ले प्रणाली के माध्यम से डिजिटल विज्ञापन को सक्षम बनाती है। इसके अतिरिक्त, मौजूदा दिशानिर्देशों के तहत रेलगाड़ियों और डिब्बों (अंदर और बाहर दोनों) जैसी चल संपत्तियों का उपयोग ब्रांडिंग और विज्ञापन के लिए किया गया है।

विज्ञापन से अर्जित राजस्व विविध राजस्व का एक हिस्सा है। खंडवार राजस्व विवरण भारतीय रेलवे के वार्षिक सांख्यिकी विवरण में उपलब्ध है। सभी विज्ञापन अनुबंध भारतीय रेलवे ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम (आईआरईपीएस) ऑनलाइन पोर्टल पर ई-नीलामी के माध्यम से दिए जाते हैं। बोलीदाता का चयन वाणिज्यिक आय और गैर-किराया राजस्व नीति तथा संबंधित अनुबंध की विशेष शर्तों के अनुसार किया जाता है, जो विज्ञापनदाताओं के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित करती हैं।

रेलगाड़ियों में प्रदर्शित विज्ञापनों के लिए, प्रत्येक विज्ञापन योजना की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है और इसे संबंधित रेलवे मंडल के मंडल प्राधिकरण के कार्यालय में जमा करना होता है। हालांकि, विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिए ब्रांड का चयन विज्ञापन एजेंसी का विशेषाधिकार है। विज्ञापन एजेंसियों को विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिए केंद्र/राज्य के कानूनों का पालन करना अनिवार्य है। कानून की दृष्टि से आपत्तिजनक विज्ञापन प्रतिबंधित हैं।

रेलगाड़ियों के अंदर/बाहर निम्नलिखित विज्ञापन प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं है:

- मदिरा के विज्ञापन
- कामुक पृष्ठभूमि वाले विज्ञापन
- अन्य परिवहन साधनों के प्रतिस्पर्धी विज्ञापन
- रेलवे दुर्घटनाओं के लिए बीमा पॉलिसी देने वाली निजी बीमा कंपनियों के विज्ञापन
- सिगरेट, बीड़ी और अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन

उत्तर रेलवे महाप्रबंधक ने केंद्रीय अस्पताल नई दिल्ली का किया निरीक्षण, सुविधाओं की समीक्षा

सूत्र/रे.स.ब्यू - उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक श्री राजेश कुमार पांडे ने नई दिल्ली स्थित केंद्रीय अस्पताल (NRCH) का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तृत आकलन किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मरीजों को दी जा रही चिकित्सा सेवाओं, बुनियादी ढांचे तथा अस्पताल में उपलब्ध अन्य सुविधाओं की स्थिति का जायजा लिया।

इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए महाप्रबंधक ने मरीजों की सुविधा और उपचार की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को निर्देशित किया कि मरीजों को समयबद्ध और प्रभावी चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं तथा किसी भी प्रकार की कमी को शीघ्र दूर किया जाए।

निरीक्षण के दौरान अस्पताल में साफ-सफाई, चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता और स्टाफ की कार्यप्रणाली पर भी विशेष ध्यान दिया गया। महाप्रबंधक ने यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि रेलवे कर्मचारियों और उनके परिजनों को उच्च स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं मिलती रहें।

जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर अनुरक्षण सुविधाओं के विस्तार के क्रम में 128.25 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक कोचिंग मेंटेनेंस डिपो की कमीशनिंग, रेल संरक्षा होगी सुदृढ़ और संचालन को मिलेगी गति

सूत्र/रे.स.ब्यू - उत्तर पश्चिम रेलवे ने जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन अनुरक्षण सुविधाओं के विस्तार के क्रम में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए ट्रिप शेड, कोचिंग मेंटेनेंस सुविधाएं, व्हील लेथ लाइन तथा सिग्नलिंग कार्य का नॉन-इंटरल किंग (NI) के साथ सफलतापूर्वक कमीशनिंग कर लिया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार जैसलमेर में अनुरक्षण सुविधाओं का विस्तार करने के लिए महाप्रबंधक श्री अमिताभ के दिशा निर्देशानुसार कोचिंग मेंटनेंस डिपो के कार्य पूर्ण किए गए हैं, जिससे स्थानीय रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी और क्षेत्र में अधिक ट्रेनों का संचालन किया जाना संभव हो सकेगा।

जैसलमेर में कोचिंग मेंटेनेंस सुविधाओं का विस्तार करने हेतु कार्य कुल लागत 128.25 करोड़ रुपये की लागत के साथ स्वीकृत किया गया था। जिसमें व्हील लेथ लाइन एवं अन्य संबंधित सुविधाएं, इलेक्ट्रिक लोको ट्रिप शेड और उससे जुड़े अन्य कार्य सम्मिलित है। इन कार्यों के अंतर्गत व्यापक स्तर पर ट्रैक एवं सिविल कार्य किए गए, जिनमें 4.8 ट्रैक किलोमीटर (TKM) ट्रैक बिछाया गया, जिससे कुल प्रभावी लंबाई 8.2 TKM हो गई। इसके साथ ही 16 नए टर्नआउट स्थापित किए गए और 650 AT वेल्डिंग कार्य पूरे किए गए। इन्फ्रास्ट्रक्चर के विस्तार हेतु 2400 वर्ग मीटर का विशाल मुख्य शेड और 1600 वर्ग मीटर के सहायक भवन तैयार किए गए, जो तकनीकी और प्रशासनिक कार्यों में उपयोगी होंगे। ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन (TRD) कार्यों के अंतर्गत संपूर्ण विद्युत वितरण प्रणाली का सफल क्रियान्वयन किया गया और एक नया टावर वैगन साइडिंग भी उपलब्ध कराया गया। सिग्नल एवं दूरसंचार (S&T) कार्यों में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, जहां नॉन-इंटरल किंग के साथ सिग्नलिंग कार्य पूरा किया गया। इसके परिणामस्वरूप स्टेशन पर रूट्स की संख्या 56 से बढ़कर 108 हो गई है, साथ ही एक लेवल क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया गया है।

इन अत्याधुनिक सुविधाओं के शुरू होने से जैसलमेर में कोचों के रखरखाव की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे नई ट्रेनों के संचालन की संभावनाएं बढ़ेंगी। नई पिट लाइन के माध्यम से कोचों का उच्च गुणवत्ता वाला प्राथमिक रखरखाव और अंडरकैरेज संरक्षा निरीक्षण सुनिश्चित होगा। वहीं ट्रिप शेड में लोकोमोटिव का अनुरक्षण किया जाना संभव हो सकेगा। यह अनुरक्षण संबंधित कार्य न केवल मेंटेनेंस समय को कम करेंगे, बल्कि होल्डिंग क्षमता बढ़ाएंगे और रेल संचालन की संरक्षा एवं विश्वसनीयता को नए स्तर तक पहुंचाएंगे। यह कार्य क्षेत्र में रेल अवसंरचना के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

भारतीय रेल यातायात सेवा अधिकारी प्रशिक्षुओं ने ओसीसी-प्रयागराज में क्षेत्रीय ज्ञान बढ़ाया: भारतीय रेल के भविष्य के उत्कृष्ट संचालन की ओर एक कदम

सूत्र/रे.स.ब्यू - 27 मार्च 2026 को भारतीय रेल ट्रैफिक सेवा (IRTS) प्रशिक्षु अधिकारियों ने लखनऊ के भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान (IRITIM) के व्यापक प्रशिक्षण मॉड्यूल के तहत प्रयागराज ऑपरेशन्स कंट्रोल सेंटर (OCC-PRYJ) का दौरा किया। इस पहल का उद्देश्य भारतीय रेल के भविष्य के नेतृत्वकर्ताओं को जरूरी क्षेत्रीय जानकारी, परिचालन विशेषज्ञता और Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited (DFCCIL) द्वारा अपनाई जाने वाली व्यावसायिक प्रथाओं की समझ प्रदान करना था। प्रशिक्षण सत्र में श्री मन्नू प्रकाश दूबे, महाप्रबंधक - परिचालन और व्यवसाय विकास, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (EDFC), श्री अकांशु गोविल, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक (समन्वय), प्रयागराज , एनसीआर, श्री मयंक राणा, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक (गुड्स), प्रयागराज , एनसीआर , श्री वैभव त्रिवेदी, DOM (गुड्स), PRYJ, NCR, श्री अंकित अग्रवाल, DCM/PRYJ/NCR और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देशित इंटरएक्टिव चर्चाओं की श्रृंखला थी।

ट्रेन संचालन की जटिलताओं, इंटरचेंज प्रोटोकॉल और DFCCIL के समग्र ढाँचे पर उनके विचारों ने प्रशिक्षुओं को आधुनिक रेलवे परिदृश्य का समेकित दृश्य प्रदान किया। श्री मन्नू प्रकाश दूबे ने रेलवे संचालन को निर्बाध बनाए रखने में OCC की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। जमीनी स्तर पर ट्रेन संचालन की वास्तविकताओं को समझना इन प्रशिक्षुओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह रेलवे परिवहन नेटवर्क की जटिलताओं को सम्हालने में सक्षम नई पीढ़ी के नेताओं के निर्माण की दिशा में पहला कदम है। प्रशिक्षुओं को EDFC ट्रेन संचालन के बारे में भी अवगत कराया गया, जिसने क्षेत्र में माल परिवहन की कार्यकुशलता में महत्वपूर्ण रूप से परिवर्तन लाया है। सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं और अत्याधुनिक तकनीक के साथ, EDFC ने न केवल डिलीवरी समय में सुधार किया है, बल्कि रसद लागत में भी महत्वपूर्ण कमी में योगदान दिया है।

श्री शशिकांत द्विवेदी, प्रधान महाप्रबंधक (इलेक्ट्रिकल), PRYJ ने बताया कि हमारे संचालन में उन्नत विद्युत प्रणालियों के समेकन ने एक हरित और अधिक कुशल रेलवे के मार्ग को प्रशस्त किया है, जो वही भविष्य है जिसके लिए हम प्रयासरत हैं। अधिवेशन में रेल संचालन में जनसम्पर्क के महत्व को भी संक्षेप में प्रस्तुत किया गया, जिसे उत्तर मध्य रेल (NCR) के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी श्री शशि कांत त्रिपाठी ने रेखांकित किया। प्रभावी संचार जनता और हितधारकों के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखने की कुंजी है। हमारा कार्य यह सुनिश्चित करना है कि समुदाय हमारे संचालन के लाभों को समझे और यह जान सके कि वे व्यापक अर्थव्यवस्था में किस तरह योगदान देते हैं। मुख्य चर्चाओं के साथ-साथ प्रशिक्षणार्थियों ने दिन-प्रतिदिन के संचालन को दर्शाने वाले व्यावहारिक अनुभवों में भी भाग लिया, जिनसे उन्हें रेलवे प्रोफेशनल्स द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों की वास्तविक समझ प्राप्त हुई।

डीडीयू-डेहरी ऑन सोन-जपला-गढ़वा रोड-डालटनगंज-लातेहार-टोरी के रास्ते आनंद विहार और पुरुलिया के मध्य एक नई एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन

सूत्र/रे.स.ब्यू - यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर आनंद विहार और पुरुलिया के मध्य दिनांक 02.04.2026 से एक नई साप्ताहिक ट्रेन 14022/14021 आनंद विहार-पुरुलिया-आनंद विहार एक्सप्रेस का परिचालन प्रारंभ किया जा रहा है । यह नई ट्रेन आनंद विहार से प्रत्येक गुरूवार को तथा पुरुलिया से प्रत्येक शुक्रवार को परिचालित की जाएगी ।

इस नई ट्रेन का परिचालन डीडीयू-डेहरी ऑन सोन-जपला-गढ़वा रोड-डालटनगंज- बरवाडीह-लातेहार-टोरी-लोहरदगा-रांची-मुरी के रास्ते किया जाएगा। इस नई ट्रेन में प्रथम वातानुकूलित श्रेणी का 01, द्वितीय वातानुकूलित श्रेणी के 02, तृतीय वातानुकूलित श्रेणी को 06, शयनयान श्रेणी के 07, सामान्य श्रेणी के 04 कोच एवं एसएलआरडी के 02 कोच सहित कुल 22 कोच होंगे ।

गाड़ी सं. 14022 आनंद विहार-पुरुलिया एक्सप्रेस दिनांक 02.04.2026 से प्रत्येक गुरूवार को आनंद विहार से 05.00 बजे खुलकर मुरादाबाद-बरेली-लखनऊ-अयोध्या कैंट-वाराणसी के रास्ते 22.40 बजे डीडीयू, 23.24 बजे भभुआ रोड, 23.53 बजे सासाराम, शुक्रवार को 00.08 बजे डेहरी ऑन सोन, 00.55 बजे जपला, 02.30 बजे गढ़वा रोड जं., 03.13 बजे डालटनगंज, 03.43 बजे बरवाडीह, 04.20 बजे लातेहार, 05.15 बजे टोरी, 06.00 बजे लोहरडगा, 07.20 बजे रांची, 08.40 बजे मूरी रुकते हुए 10.40 बजे पुरुलिया पहुंचेगी ।

वापसी में गाड़ी सं. 14021 पुरुलिया-आनंद विहार एक्सप्रेस दिनांक 03.04.2026 से प्रत्येक शुक्रवार को पुरुलिया से 17.00 बजे खुलकर 18.18 बजे मूरी, 19.35 बजे रांची, 21.10 बजे लोहरडगा, 22.15 बजे टोरी, 22.55 बजे लातेहार, शनिवार को 00.01 बजे बरवाडीह, 00.30 बजे डालटनगंज, 01.40 बजे गढ़वा रोड जं., 02.15 बजे जपला, 03.30 बजे डेहरी ऑन सोन, 03.52 बजे सासाराम, 04.35 बजे भभुआ रोड, 05.40 बजे डीडीयू सहित अन्य स्टेशनों पर रुकते हुए 23.10 बजे आनंद विहार पहुंचेगी ।

आवश्यक सूचना

भारतीय रेल द्वारा सर्वसाधारण को सुचित किया जाता है कि ट्रैफिक एवं पॉवर ब्लॉक के कारण निम्नलिखित रेलगाड़ियों के मार्ग परिवर्तन का निर्णय लिया गया है जिसका विवरण निम्नवत् है:-

रेलगाड़ियों का मार्ग परिवर्तन

गाड़ी सं.	कहाँ से - कहाँ तक	वर्तमान मार्ग	परिवर्तित मार्ग (वाया)	प्रारंभिक स्टेशन से प्रभावी तिथि
12311	हावड़ा जं.-कालका	खुर्जा जं.-दिल्ली जं.-पानीपत जं.-अम्बाला कैण्ट	खुर्जा जं.-मेरठ सिटी-सहारनपुर-अम्बाला कैण्ट	29.05.2026 से 03.06.2026
12312	कालका-हावड़ा जं.	अम्बाला कैण्ट-पानीपत जं.-दिल्ली जं.-खुर्जा जं.	अम्बाला कैण्ट-सहारनपुर-मेरठ सिटी-खुर्जा जं.	30.05.2026 से 04.06.2026
18101	टाटानगर जं.-जम्मू तवी	खुर्जा जं.-दिल्ली जं.-पानीपत जं.-अम्बाला कैण्ट	खुर्जा जं.-मेरठ सिटी-सहारनपुर-अम्बाला कैण्ट	29.05.2026, 31.05.2026, 03.06.2026
18102	जम्मू तवी-टाटानगर जं.	अम्बाला कैण्ट-पानीपत जं.-दिल्ली जं.-खुर्जा जं.	अम्बाला कैण्ट-सहारनपुर-मेरठ सिटी-खुर्जा जं.	30.05.2026, 01.06.2026, 03.06.2026
18309	सम्बलपुर जं.-जम्मू तवी	खुर्जा जं.-दिल्ली जं.-पानीपत जं.-अम्बाला कैण्ट	खुर्जा जं.-मेरठ सिटी-सहारनपुर-अम्बाला कैण्ट	30.05.2026, 01.06.2026, 02.06.2026
18310	जम्मू तवी-सम्बलपुर जं.	अम्बाला कैण्ट-पानीपत जं.-दिल्ली जं.-खुर्जा जं.	अम्बाला कैण्ट-सहारनपुर-मेरठ सिटी-खुर्जा जं.	31.05.2026, 02.06.2026, 04.06.2026
15708	अमृतसगर जं.-कटिहार जं.	अम्बाला कैण्ट-पानीपत जं.-दिल्ली जं.-खुर्जा जं.	अम्बाला कैण्ट-सहारनपुर-मेरठ सिटी-खुर्जा जं.	06.06.2026
14218	चण्डीगढ़ जं.-प्रयागराज संगम	अम्बाला कैण्ट-पानीपत, जं.-दिल्ली जं.-खुर्जा जं.	अम्बाला कैण्ट-सहारनपुर-मेरठ सिटी-खुर्जा जं.	06.06.2026
11077	पुणे-जम्मू तवी	नई दिल्ली, पानीपत अम्बाला कैंट, लुधियाना	नई दिल्ली, शकूर बस्ती, जाखल, धूरी, लुधियाना	29.05.2026 से 03.06.2026
11095	आगरा कैंट-होशियार पुर	नई दिल्ली,पानीपत, अम्बाला कैंट, लुधियाना	नई दिल्ली, शकूर बस्ती, जाखल, धूरी, लुधियाना	30.05.2026 से 04.06.2026
12925	बान्द्रा टर्मिनस-अमृतसर	नई दिल्ली, पानीपत, अम्बाला कैंट	नई दिल्ली, दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ सिटी, सहारनपुर, अम्बाला कैंट	05.06.2026
12715	हजूर साहिब नान्देड-अमृतसर	हज़रत निज़ामुद्दीन, नई दिल्ली, पानीपत, अम्बाला कैंट	ह.निज़ामुद्दीन, तिलक ब्रिज, गाजियाबाद, सहारनपुर, अम्बाला कैंट	05.06.2026
20434	श्रीमाता वैष्णो देवी कटड़ा-सूबेदारगंज	अम्बाला कैंट, पानीपत, दिल्ली, खुर्जा	अम्बाला कैंट, सहारनपुर, मेरठ सिटी, खुर्जा	30.05.2026 से 04.06.2026
11906	होशियारपुर-आगरा कैंट	लुधियाना, अम्बाला कैंट, पानीपत, नई दिल्ली	लुधियाना, धूरी, जाखल, शकूर बस्ती, नई दिल्ली	30.05.2026 से 04.06.2026
22686	चण्डीगढ़-यशवंतपुर	अम्बाला कैंट, पानीपत, नई दिल्ली, हज़रत निज़ामुद्दीन	अम्बाला कैंट, सहारनपुर, मेरठ सिटी, गाजियाबाद, तिलक ब्रिज, ह.निज़ामुद्दीन	02.06.2026
20808	अमृतसर-विशाखा-पट्टणम	अम्बाला कैंट, पानीपत, नई दिल्ली, हज़रत निज़ामुद्दीन	अम्बाला कैंट, सहारनपुर, मेरठ सिटी, गाजियाबाद, तिलक ब्रिज, ह.निज़ामुद्दीन	30.05.2026, 31.05.2026, 03.06.2026
12926	अमृतसर-बान्द्रा टर्मिनस	अम्बाला कैंट, पानीपत, नई दिल्ली, हज़रत निज़ामुद्दीन	अम्बाला कैंट, सहारनपुर, मेरठ सिटी, गाजियाबाद, तिलक ब्रिज, ह.निज़ामुद्दीन	06.06.2026

नोटः ट्रेनों की समय-सारणी के सम्बन्धित जानकारी हेतु हेल्पलाइन 139 या Rail madad Mobile App या वेबसाइट railmadad.indianrailways.gov.in का प्रयोग करें।

उत्तर मध्य रेलवे

@CPRONCR North central railways www.ncr.indianrailways.gov.in 686/26 FA

भारतीय रेलवे के महत्वपूर्ण वड़ोदरा - नागदा सेक्शन पर 'कवच 4.0' का सफलतापूर्वक कमीशन

वड़ोदरा- नागदा रेलखंड पर कवच प्रणाली से लैस पहली स्पेशल ट्रेन का संचालन

मुंबई - नई दिल्ली मुख्य मार्ग का अधिकतम रुट अब कवच प्रणाली से परिपूर्ण

सूत्र/रे.स.ब्यू - भारतीय रेलवे द्वारा रेल परिचालन में संरक्षा को और मजबूत करने के क्रम में 30 मार्च, 2026 को वडोदरा - नागदा सेक्शन पर कवच 4-0 सिस्टम को सफलतापूर्वक कमीशन किया गया। इस अवसर पर वडोदरा स्टेशन से कवच प्रणाली से लैस स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गयी। इस प्रकार मिशन रफ्तार के अंतर्गत मुंबई - नई दिल्ली मुख्य मार्ग के पश्चिम रेलवे के निर्धारित 693 रुट किलोमीटर में से 559.5 रुट किलोमीटर पर यानी अधिकतम रुट पर इस प्रणाली को स्थापित किया जा चुका है।

वडोदरा - नागदा सेक्शन के अंतर्गत वडोदरा से मंगल महुडी सेक्शन (122.5 Rkm) और पंचपिपलिया - नागदा (102.01 Rkm) सेक्शन के बीच में यानी कुल 224.51 रुट किलोमीटर पर कवच प्रणाली को आज सफलतापूर्वक लांच किया गया है। मंगल महुडी से पंचपिपलिया के बीच इस प्रणाली को स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है और जल्द ही इसे आटोमेटिक सिगनलिंग के साथ पूरा कर लिया जायेगा। वडोदरा मंडल द्वारा इससे पहले जनवरी 2026 में वडोदरा - विरार सेक्शन पर कवच सिस्टम चालू किया गया था और आज वडोदरा से गोधरा होते हुए नागदा तक इसे कमीशन किया गया है।

कवच एक ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है और यह मानवीय गलतियों के जोखिम को कम करने के लिए ट्रेन सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत है। जो कि मानवीय त्रुटि के कारण 'सिग्नल पासिंग एट डेंजर' (SPAD) से होने वाले परिणामों को रोकती है।

वडोदरा नागदा सेक्शन पर इस जटिल कार्य के निष्पादन हेतु प्रत्येक स्टेशन तथा प्रत्येक एब्सोल्यूट/ऑटोमैटिक सिग्नलिंग सेक्शन के लिए पृथक योजना तैयार की गई, पटरियों पर 6000 से अधिक स्थानों पर RFID टैग का प्रोग्रामिंग एवं स्थापना कार्य किया गया, 26 स्टेशनों, 13 मध्य-खंडों तथा लोकोमोटिव के बीच सतत रेडियो संचार की व्यवस्था सुनिश्चित की गई, प्रत्येक स्टेशन पर कुल 39 रेडियो संचार टावर एवं आवश्यक उपकरण स्थापित किए गए, पूरे मार्ग पर UP एवं DN दोनों दिशाओं में लगभग 600 किमी लंबाई की OFC केबल बिछाई गई, साथ ही प्रत्येक स्टेशन, मध्य-खंड एवं LC गेट पर आधुनिक 'कवच' उपकरण स्थापित कर उन्हें मौजूदा सिग्नलिंग प्रणाली से एकीकृत किया गया, लोकोमोटिव में भी 'कवच' उपकरण लगाए गए तथा अंततः संपूर्ण प्रणाली का सफलतापूर्वक ट्रायल एवं परीक्षण किया गया।

'कवच' प्रणाली अपने यूरोपीय समकक्षों (ETCS) की तुलना में बहुत सस्ती है। अभी तक WAP-7, WAG9, WAP5 लोकोमोटिव में कवच प्रणाली लगाई गयी है। जल्द ही, इसे दूसरे लोकोमोटिव पर भी शुरू किया जाएगा।

भारतीय रेलवे आधुनिक एवं स्वदेशी तकनीकों को अपनाकर सुरक्षित, दक्ष एवं भविष्य उन्मुख रेल नेटवर्क के निर्माण हेतु निरंतर प्रतिबद्ध है।

डिजिटल उत्तर प्रदेश की ओर एक और कदम- 'कौशल दोस्त' बना युवाओं का नया मार्गदर्शक

सूत्र/रे.स.ब्यू -उत्तर प्रदेश में कौशल विकास को सरल, सुलभ और प्रभावी बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत 'कौशल दोस्त' नामक एआई आधारित चौटबॉट की शुरुआत की है, जो युवाओं को 24X7 सहायता प्रदान करेगा।

डिजिटल तकनीक के इस युग में जहां समय की बचत और त्वरित जानकारी अत्यंत आवश्यक हो गई है, वहीं 'कौशल दोस्त' युवाओं के लिए एक भरोसेमंद डिजिटल साथी बनकर उभरा है। अब स्किल ट्रेनिंग, कोर्स, पंजीकरण या प्रशिक्षण केंद्रों से जुड़ी जानकारी के लिए किसी कार्यालय के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। युवा घर बैठे ही आधिकारिक वेबसाइट www.upsdm.gov.in के माध्यम से अपने सभी सवालों के जवाब तुरंत प्राप्त कर सकेंगे।

यह ए०आई० आधारित चौटबॉट इस प्रकार विकसित किया गया है कि यह सरल भाषा में सटीक और उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराता है। चाहे किसी को प्रशिक्षण में पंजीकरण की प्रक्रिया जाननी हो, उपलब्ध कोर्स और सेक्टर की जानकारी चाहिए हो, या फिर अपने नजदीकी प्रशिक्षण केंद्रों की सूची देखनी हों 'कौशल दोस्त' हर समय सहायता के लिए तैयार है। इससे प्रदेश के दूर-दराज क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं को भी बिना किसी कठिनाई के कौशल विकास योजनाओं से जुड़ने का अवसर मिलेगा।

रेल की हर अपडेट अब आपके मोबाइल पर

बस स्कैन करें यह कोड

रेल समाचार ब्यूरो की वेबसाइट पर खबरें पढ़ने के लिए अभी स्कैन करें

आयुष मंत्रालय और डीबीटी ने आयुर्वेद में तपेदिक (टीबी) के उपचार में सहायक चिकित्सा के रूप में एक संयुक्त नैदानिक अध्ययन की घोषणा की

तपेदिक उन्मूलन का अर्थ केवल संख्या कम करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक रोगी स्वास्थ्य, सम्मान और शक्ति के साथ जीवन व्यतीत करे: आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री प्रतापराव जाधव

सूत्र/रे.स.ब्यू - विश्व क्षय रोग (टीबी) दिवस के अवसर पर, केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) के साथ साझेदारी में ''आयुर्वेद में तपेदिक के लिए सहायक चिकित्सा के रूप में नैदानिक अध्ययन'' शीर्षक से एक सहयोगी नैदानिक अध्ययन की औपचारिक घोषणा के साथ एकीकृत स्वास्थ्य सेवा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह और आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव ने मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों और वैज्ञानिकों की उपस्थिति में इस बारे में संयुक्त रूप से घोषणा की। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित इस उच्च स्तरीय कार्यक्रम में प्रमुख नीति निर्माता, वैज्ञानिक, विद्वान, शोधकर्ता, चिकित्सक और अन्य महत्वपूर्ण हितधारक भी एकत्रित हुए, ताकि तपेदिक के खिलाफ लड़ाई में पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा के साक्ष्य-आधारित एकीकरण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया जा सके। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने अपने संबोधन में कहा, "भारत तपेदिक के खिलाफ लड़ाई में सही दिशा में आगे बढ़ रहा है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में समर्पित तथा नवोन्मेषी प्रयासों के कारण तपेदिक के मामलों में उल्लेखनीय कमी आई है।" उन्होंने कहा, "इस सहयोगात्मक नैदानिक अध्ययन का शुभारंभ विज्ञान-आधारित, साक्ष्य-आधारित नवाचार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो आधुनिक जैव चिकित्सा अनुसंधान को मान्य पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों के साथ एकीकृत करता है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में की गई पहलों के माध्यम से, हम अनुसंधान को मजबूत कर रहे हैं, वैश्विक साझेदारियों को बढ़ावा दे रहे हैं और दवा प्रतिरोध, कुपोषण तथा तपेदिक के दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभावों जैसी चुनौतियों का समाधान करने के लिए रोगी-केंद्रित समाधानों को आगे बढ़ा रहे हैं।"

आयुष मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव ने अपने संबोधन में जोर देते हुए कहा: "तपेदिक का उपचार केवल संक्रमण को समाप्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि रोगी को पूर्णतः स्वस्थ बनाने के बारे में भी है। इस दृष्टिकोण के साथ, हम एक नए परिप्रेक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ आयुर्वेद और अन्य आयुष प्रणालियाँ न केवल उपचार में सहायक हैं, बल्कि रोगियों के स्वास्थ्य लाभ, पोषण और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।"

कार्यक्रम का शुभारंभ डीबीटी के सचिव, बीआरआईसी के महानिदेशक और बीआईआरएसी के अध्यक्ष डॉ. राजेश एस. गोखले के उद्घाटन भाषण से हुआ। उन्होंने कहा, "भारत में तपेदिक अनुसंधान ने निदान, टीकों और बड़े पैमाने पर किए गए विभिन्न अध्ययनों में नवाचार के माध्यम से उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आयुष मंत्रालय के साथ यह सहयोगात्मक कार्यक्रम एकीकृत, साक्ष्य-आधारित स्वास्थ्य सेवा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आधुनिक विज्ञान को आयुर्वेद के साथ मिलाकर, हमारा उद्देश्य रोगियों के उपचार परिणामों में सुधार करना, जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना और भारत के तपेदिक उन्मूलन मिशन को गति देना है।"

> तपेदिक उन्मूलन का अर्थ केवल संख्या कम करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक रोगी स्वास्थ्य, सम्मान और शक्ति के साथ जीवन व्यतीत करे: आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री प्रतापराव जाधव

आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने इसके बाद अपने विचार व्यक्त किए। श्री कोटेचा ने कहा, "तपेदिक प्रबंधन के लिए न केवल प्रभावी उपचार बल्कि स्वास्थ्य लाभ और जीवन की गुणवत्ता पर भी ध्यान देना आवश्यक है। आयुष-डीबीटी की यह संयुक्त पहल साक्ष्य-आधारित एकीकृत स्वास्थ्य सेवा के लिए हमारी प्रतिबद्धता दर्शाती है। आयुर्वेद को विज्ञान के साथ जोड़कर, हमारा उद्देश्य तपेदिक से संबंधित दुर्बलता को दूर करना, रोगियों के स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाना और भारत के तपेदिक उन्मूलन के लक्ष्य में सार्थक योगदान देना है।"

आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस) के महानिदेशक प्रोफेसर वैद्य रबीनारायण आचार्य और बीआरआईसी-राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान (एनआईआई) के निदेशक डॉ. देबासिसा मोहंती ने सहयोगात्मक नैदानिक अध्ययन का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। प्रस्तुति में अध्ययन की वैज्ञानिक रूपरेखा, उद्देश्य और अपेक्षित परिणामों का विस्तार से वर्णन किया गया, जिसका उद्देश्य मानक तपेदिक रोधी उपचार (एटीटी) के साथ-साथ वृक्क पोषक तत्वों के पूरक के रूप में आयुर्वेद पद्धति की प्रभावकारिता, सुरक्षा और सहनशीलता का मूल्यांकन करना है।

यह सहयोगात्मक नैदानिक अध्ययन आयुष मंत्रालय और जैव प्रौद्योगिकी विभाग की एक संयुक्त पहल है, जो मई 2022 में एकीकृत और साक्ष्य-आधारित स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन पर आधारित है। आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस) के नेतृत्व में और डीबीटी के सहयोग से संचालित यह बहु-केंद्रीय अध्ययन, पोषण संबंधी सहायता के साथ-साथ मानक तपेदिक-रोधी उपचार (एटीटी) के पूरक के रूप में आयुर्वेद उपचार की प्रभावकारिता, सुरक्षा और सहनशीलता का मूल्यांकन करेगा। एम्स, जेआईपीएमईआर और एनईआईजीआरआईएचएमएस सहित प्रमुख संस्थानों में आयोजित होने वाले इस 24 महीने के अध्ययन का उद्देश्य तपेदिक रोगियों में पोषण संबंधी परिणामों में सुधार, शीघ्र स्वस्थ होने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के संबंध में ठोस वैज्ञानिक प्रमाण जुटाना है, जिससे तपेदिक उन्मूलन के लिए नवीन, रोगी-केंद्रित दृष्टिकोणों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को और मजबूती मिलेगी।

इस कार्यक्रम का एक प्रमुख आकर्षण ब्रिक-ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट (टीएचएसटीआई) और सीसीआरएएस के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) का आदान-प्रदान था, जिसने संस्थागत सहयोग को औपचारिक रूप दिया। समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान ब्रिक-टीएचएसटीआई के कार्यकारी निदेशक प्रो. जी. कार्तिकेयन और सीसीआरएएस के महानिदेशक प्रो. वैद्य रबीनारायण आचार्य के बीच हुआ।

कार्यक्रम का समापन भारत सरकार की जटिल सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों के समाधान के लिए एकीकृत, साक्ष्य-आधारित स्वास्थ्य देखभाल समाधानों को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता की ढ़तापूर्वक पुष्टि के साथ हुआ। आयुष-डीबीटी सहयोगात्मक पहल से टीबी की सहायक देखभाल में नई वैज्ञानिक सुझाव और विचार प्राप्त होने की संभावना है, साथ ही बेहतर रोगी परिणामों और टीबी उन्मूलन की दिशा में त्वरित प्रगति के लिए पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक जैव चिकित्सा अनुसंधान के साथ जोड़ने में भारत के नेतृत्व को सुदृढ़ किया जाएगा।

निवारक स्वास्थ्य देखभाल और आरोग्य को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के बीच साझेदारी

सूत्र/रे.स.ब्यू - सुरक्षा बलों के बीच निवारक स्वास्थ्य देखभाल और समग्र स्वास्थ्य देखभाल की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, आयुष मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआई- एसएफ) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य सीआईएसएफ कर्मियों और उनके परिवारों के बीच आयुष-आधारित निवारक स्वास्थ्य देखभाल, आरोग्य, योग, तनाव कम करने और समग्र स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना है।

इस समझौते पर आयुष मंत्रालय के सलाहकार (आयु.) डॉ. ए.रघु और सीआईएसएफ मुख्यालय, नई दिल्ली की महानिरीक्षक (प्रशासन) श्रीमती प्रतिभा अग्रवाल ने हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर समारोह आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा और सीआईएसएफ के महानिदेशक श्री प्रवीर रंजन (आईपीएस) और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ।

इस समझौते का उद्देश्य दोनों संगठनों के बीच समन्वय को बढ़ाना है ताकि सीआईएसएफ कर्मियों को आयुष-आधारित निवारक, संवर्धनात्मक और आरोग्य सेवाएं प्रदान की जा सकें। इसके मुख्य फोकस क्षेत्रों में जागरूकता पैदा करना, आयुष की जानकारी देने, आरोग्य समाधानों, योग अभ्यास, जीवनशैली सुधार और आयुष प्रणालियों के माध्यम से समग्र स्वास्थ्य देखभाल शामिल है। यह पहल सीआईएसएफ के प्रतिष्ठानों में, जहाँ भी संभव हो, आयुष ओपीडी सेवाएं प्रदान करने की संभावनाओं पर भी विचार करेगी। इस समझौता ज्ञापन की शर्तों के तहत, आयुष मंत्रालय तकनीकी सहायता प्रदान करेगा, आरोग्य मॉड्यूल विकसित करेगा और अपने संस्थानों एवं अनुसंधान परिषदों के माध्यम से विशेषज्ञ मार्गदर्शन उपलब्ध कराएगा। दूसरी ओर, सीआईएसएफ अपनी विभिन्न इकाइयों और प्रतिष्ठानों में इन पहलों के कार्यान्वयन को सुगम बनाएगा।

यह साझेदारी सुरक्षाकर्मियों के दैनिक जीवन में चिकित्सा की पारंपरिक प्रणालियों को एकीकृत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे उनके स्वास्थ्य, जुझारूपन और जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार होगा। यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए जाने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा।

संपादकीय

दूरदराज क्षेत्रों के विकास में रेलवे की भूमिका

भारत जैसे विशाल देश में समावेशी विकास का अर्थ तभी पूरा होता है जब दूरदराज और पिछड़े क्षेत्रों तक भी प्रगति की धारा पहुंचे। इस दिशा में भारतीय रेलवे ने एक सशक्त माध्यम के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। रेलवे केवल यात्रियों और माल के परिवहन का साधन नहीं, बल्कि यह देश के आर्थिक और सामाजिक एकीकरण की रीढ़ है।

दूरस्थ क्षेत्रों में रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ने से सबसे बड़ा लाभ स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलता है। जहां पहले किसान और छोटे व्यापारी सीमित बाजारों तक ही सीमित रहते थे, वहीं अब वे अपने उत्पादों को बड़े शहरों और अन्य राज्यों तक आसानी से भेज पा रहे हैं। इससे उनकी आय में वृद्धि होती है और क्षेत्रीय असमानता कम करने में मदद मिलती है। पूर्वोत्तर भारत, जम्मू-कश्मीर और आदिवासी क्षेत्रों में रेल नेटवर्क का विस्तार इस बदलाव का स्पष्ट उदाहरण है।

रेलवे परियोजनाएं रोजगार सृजन का भी एक बड़ा स्रोत हैं। नई रेल लाइनों के निर्माण, स्टेशनों के विकास और संचालन से स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलता है। साथ ही, रेलवे स्टेशनों के आसपास छोटे व्यवसायें जैसे दुकानें, भोजनालय और परिवहन सेवाएँ तेजी से विकसित होते हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिलती है।

सामाजिक दृष्टि से भी रेलवे का योगदान महत्वपूर्ण है। दूरदराज क्षेत्रों के लोगों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान हो जाती है। अब वे बेहतर इलाज और उच्च शिक्षा के लिए बड़े शहरों की यात्रा आसानी से कर सकते हैं। इससे जीवन स्तर में सुधार होता है और समाज में नई संभावनाएं जन्म लेती हैं।

हालांकि, इस विकास के रास्ते में चुनौतियां भी हैं। कठिन भौगोलिक परिस्थितियां, पर्यावरणीय संतुलन और परियोजनाओं में देरी जैसे मुद्दे अक्सर बाधा बनते हैं। इसलिए जरूरी है कि विकास कार्यों में पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय संस्कृति का भी ध्यान रखा जाए।

अंततः, रेलवे दूरदराज क्षेत्रों के विकास का एक मजबूत आधार है। यदि योजनाबद्ध और संतुलित तरीके से इसका विस्तार जारी रखा जाए, तो यह न केवल कनेक्टिविटी बढ़ाएगा, बल्कि एक समावेशी और सशक्त भारत के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

भारतीय रेलवे ने दिल्ली-हावड़ा उच्च घनत्व वाले गलियारे के प्रयागराज-कानपुर खंड के 190 किलोमीटर मार्ग पर कवच प्रणाली का उद्घाटन किया

सूत्र/रे.स.ब्यू - भारतीय रेलवे ने 22 मार्च 2026 को दिल्ली-हावड़ा उच्च घनत्व वाले कॉरिडोर के प्रयागराज-कानपुर (दोनों स्टेशनों को छोड़कर) खंड (190 किलोमीटर) पर कवच स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (एटीपी) प्रणाली को सफलतापूर्वक चालू कर दिया। कवच प्रणाली को ट्रेन संख्या 14163 के जरिए लागू किया गया। महाप्रबंधक ने कवच प्रणाली के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए सूबेदारगंज से मनौरी स्टेशन तक ट्रेन संख्या 14163 में फुटप्लेट निरीक्षण भी किया। इस अवसर पर पीएचओडी, डीआरएम/ प्रयागराज, मुख्यालय के अधिकारी और मंडल अधिकारी सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

पहले चरण में, कवच प्रणाली आठ जोड़ी ट्रेनों में शुरू की जाएगी : 14113/14114, 14163/14164, 12307/12308, 12417/12418, 22437/22438, 15003/15004, 20433/20434 और 12403/12404)। अतिरिक्त ट्रेनों और वंदे भारत प्रणाली को इसमें धीरे-धीरे शामिल किया जाएगा।

इस प्रणाली के शुरू होने से भारतीय रेलवे के सबसे अहम खंडों में से एक पर 160 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें चलाने, रेलवे सुरक्षा बढ़ाने और परिचालन दक्षता में सुधार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है।

इस प्रक्रिया को शुरू करने से पहले, व्यापक और कठोर परीक्षण सफलतापूर्वक किए गए। परीक्षण में 8, 16 और 22 एलएचबी कोच कॉन्फिगरेशन वाले डब्ल्यूएपी-7 लोकोमोटिव के साथ-साथ 20 कोच वाली वंदे भारत रेक का उपयोग किया गया, जिससे विभिन्न परिचालन स्थितियों में प्रणाली की विश्वसनीयता मापी गई। डब्ल्यूएपी-7 एक उच्च-प्रदर्शन वाला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है, जिसका उपयोग भारतीय रेलवे द्वारा यात्री ट्रेनों को खींचने के लिए किया जाता है, जिसमें राजधानी, शताब्दी और दुरंतो एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम सेवाएं शामिल हैं।

ट्रेन संख्या 15003/15004 (चौरी चौरा एक्सप्रेस) का उपयोग करते हुए यात्री परीक्षण भी किए गए, जिसने नियमित सेवा के दौरान लगातार और विश्वसनीय प्रदर्शन किया। 20,000 किलोमीटर से अधिक के यात्री परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए जा चुके हैं और सभी सिस्टम सत्यापन संतोषजनक पाए गए हैं। कवच, मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, जिसे भारतीय रेलवे में सुरक्षा बढ़ाने और ट्रेन संचालन को आधुनिक बनाने के लिए धीरे-धीरे लागू किया जा रहा है। इससे पहले, व्यापक और विस्तृत परीक्षणों के बाद, कवच संस्करण 4.0 को दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-हावड़ा जैसे व्यस्त मार्गों सहित 1,452 किलोमीटर मार्गों पर सफलतापूर्वक चालू किया जा चुका है। भारतीय रेलवे आधुनिक सुरक्षा प्रौद्योगिकियों को अपनाने और सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि यात्रियों के लिए सुरक्षित, अधिक विश्वसनीय और कुशल ट्रेन संचालन सुनिश्चित किया जा सके।

अगले चरण में, मिशन रफ्तार के उद्देश्यों में से एक के रूप में, गाजियाबाद-टुंडला खंड में 160 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें चलाने के लिए कवच प्रणाली शुरू की जाएगी।

क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 72वीं बैठक का आयोजन 'राजभाषा सरिता' के 56वें अंक का विमोचन

सूत्र/रे.स.ब्यू- क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति, पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर की 72वीं बैठक दिनांक 25.03.2026 को समिति अध्यक्ष एवं महाप्रबंधक श्री प्रमोद कुमार खत्री की अध्यक्षता में संपन्न हुई। अपने अध्यक्षीय संबोधन में महाप्रबंधक ने कहा कि भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुरूप सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी को प्रेरणा एवं प्रोत्साहन से आगे बढ़ाया जाए। मुझे खुशी है कि पश्चिम मध्य रेलवे पर राजभाषा हिंदी के प्रयोग-प्रसार में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उन्होंने सबका आव्हान करते हुए कहा कि हिंदी का प्रचार-प्रसार व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी है। इसके लिए सभी को प्रयास करने होंगे। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों एवं कार्यालय प्रमुखों से विभिन्न राजभाषा मदों पर अमल कर कार्रवाई करने को कहा।

बैठक के दौरान राजभाषा विभाग, पश्चिम मध्य रेलवे, मुख्यालय, जबलपुर की त्रैमासिक राजभाषा पत्रिका 'राजभाषा सरिता' के 56वें अंक का विमोचन किया गया। बैठक में मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण) श्री एम.एस. हाशमी ने समीक्षाधीन तिमाही में मुख्यालय, मंडलों एवं कारखानों में आयोजित कार्यक्रमों समिति अध्यक्ष एवं सदस्यों को अवगत कराया। उन्होंने रेलवे बोर्ड स्तर पर पमरे मुख्यालय को रेल मंत्री राजभाषा शील्ड प्राप्त होने पर बधाई दी।

इस बैठक में समिति सदस्य एवं विभाग प्रमुख तथा मंडलों के अपर मंडल रेल प्रबंधक व कारखानों के मुख्य कारखाना प्रबंधक ऑन लाइन उपस्थित थे। सभी ने विभागों, मंडलों तथा कारखानों में सरकारी कामकाज में हुई राजभाषा प्रगति से अध्यक्ष / महाप्रबंधक को अवगत कराया तथा रचनात्मक सुझाव दिये। बैठक का संचालन संतलाल मर्सकोले, वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी ने किया।

ऑनलाइन रेलवे टिकटिंग में तेज उछाल, 88% आरक्षित टिकट अब डिजिटल माध्यम से बुक

सूत्र/रे.स.ब्यू - भारतीय रेलवे में ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्रणाली की लोकप्रियता में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जहां वित्त वर्ष 2025-26 में 26 फरवरी तक कुल 48.25 करोड़ आरक्षित टिकट ऑनलाइन माध्यम से बुक किए गए, जो कुल बुकिंग का लगभग 88% हिस्सा है। इसके मुकाबले काउंटर से केवल 6.15 करोड़ टिकट ही बुक हुए, जिससे डिजिटल प्लेटफॉर्म की बढ़ती स्वीकार्यता स्पष्ट होती है।

इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) द्वारा संचालित इस प्रणाली ने यात्रियों को आरक्षण काउंटर पर जाने की आवश्यकता से मुक्त किया है, जिससे समय और परिवहन लागत दोनों में बचत हुई है। हालांकि, इस सुविधा के संचालन, रखरखाव और उन्नयन के लिए आईआरसीटीसी द्वारा मामूली सुविधा शुल्क लिया जाता है। टिकट बुकिंग प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए कई तकनीकी और प्रशासनिक उपाय लागू किए गए हैं। 1 जुलाई 2025 से तत्काल योजना के तहत टिकट बुकिंग केवल आधार प्रमाणित उपयोगकर्ताओं तक सीमित कर दी गई है। इसके अलावा, अग्रिम आरक्षण अवधि के पहले दिन सामान्य टिकटों की बुकिंग भी केवल आधार सत्यापित उपयोगकर्ताओं को ही उपलब्ध कराई गई है।

इन उपायों के परिणामस्वरूप टिकटों की अनुचित बुकिंग में कमी आई है और वास्तविक यात्रियों के लिए टिकट उपलब्धता में सुधार हुआ है। वर्ष 2025 के दौरान फर्जी या संदिग्ध गतिविधियों के कारण 3.04 करोड़ उपयोगकर्ता खाते बंद किए गए, जबकि 2.94 करोड़ खातों को पुनः सत्यापन के विकल्प के साथ अस्थायी रूप से निष्क्रिय किया गया। वहीं, 1 जनवरी 2025 से 28 फरवरी 2026 के बीच 1,80,474 खातों को पुनः सक्रिय किया गया। आईआरसीटीसी ने तकनीकी स्तर पर भी सख्त कदम उठाए हैं। एंटी-बॉट तकनीक के माध्यम से लगभग 64% संदिग्ध ट्रैफिक को रोका गया है, जिससे वास्तविक उपयोगकर्ताओं के लिए बुकिंग प्रक्रिया अधिक सुगम हुई है। इसके अतिरिक्त, 28 फरवरी 2026 तक 13,023 संदिग्ध ईमेल डोमेन ब्लॉक किए गए और नेशनल साइबर अपराध पोर्टल पर 4.07 लाख संदिग्ध पीएनआर से संबंधित 408 शिकायतें दर्ज की गई।

सिस्टम के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क (सीडीएन) लागू किया गया है, जिससे सर्वर पर लोड कम हुआ है और उपयोगकर्ता अनुभव बेहतर हुआ है। साथ ही, डेटा विश्लेषण के माध्यम से संदिग्ध गतिविधियों की पहचान कर उपयोगकर्ता खातों को निष्क्रिय किया जाता है और सत्यापन के बाद वास्तविक खातों को पुनः सक्रिय किया जाता है।

रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में जानकारी देते हुए कहा कि ये सभी उपाय टिकट बुकिंग प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

फार्म-IV (घोषणा)

1. प्रकाशन - प्रयागराज
2. प्रकाशन की अवधि - पाक्षिक
3. मुद्रक का नाम - ज्ञानेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
   राष्ट्रीयता - भारतीय
   पता - 502 पंचशीला त्रिवेणी नगर, नेता नगर, कीड़गंज प्रयागराज (इलाहाबाद)
4. संपादक का नाम - ज्ञानेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
   राष्ट्रीयता - भारतीय
5. उन व्यक्तियों के नाम व पते, जो समाचार पत्र की कुल पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के स्वामी हैं - ज्ञानेन्द्र कुमार श्रीवास्तव

मैं ज्ञानेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, एतद् द्वारा घोपाणा करता हूं कि उपरोकत विवरण मेरी जानकारी विश्वास के अनुसार है।

-ज्ञानेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
31 मार्च 2026

धार्मिक यात्रा का सुनहरा अवसर: भारत गौरव ट्रेन से करें दक्षिण भारत के प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन

सूत्र/रे.स.ब्यू- इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म क पोंरेशन लिमिटेड आईआरसीटीसी भारत सरकार के रेल मंत्रालय के अंतर्गत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। आईआरसीटीसी को स्टेशनों, ट्रेनों पर खानपान और आतिथ्य सेवाओं को उन्नत करने एवं पेशेवर बनाने और प्रबंधित करने और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे की एक विस्तारित शाखा के रूप में स्थापित किया गया है। इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कार्पोरेशन लि० (आईआरसीटीसी) } द्वारा गोरखपुर रेलवे स्टेशन से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन} द्वारा तिरुपति बालाजी मंदिर, रामनाथ स्वामी मंदिर (रामेश्वरम), मीनाक्षी मंदिर, कन्याकुमारी दर्शन, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, यात्रा का संचालन किया जा रहा है। इकोनामी श्रेणी (स्लीपर क्लासं) में ठहरने पर पैकेज का मूल्य रू०- 24790/- प्रति व्यक्ति एवं प्रति बच्चे (5-11 वर्ष) का पैकेज का मूल्य रू०- 23400/- है। (स्लीपर क्लास ट्रेन यात्रा, डबल/ट्रिपल पर नॉन एसी होटलों में ठहरने, नॉन एसी होटल के कमरे में मल्टी शेयर पर (शेयरिंग/नॉन शेयरिंग-पैकेज के अनुसार) वॉश एंड चेंज एवं नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था)

स्टैंडर्ड श्रेणी (3एसी क्लास) में ठहरने पर पैकेज का मूल्य रू०- 42530/- प्रति व्यक्ति एवं प्रति बच्चे (5-11 वर्ष) का पैकेज का मूल्य रू०- 40900/- है । (3एसी क्लास ट्रेन यात्रा, डबल/ट्रिपल पर एसी होटलों में ठहरने, नॉन एसी होटल के कमरे में डबल/ट्रिपल पर (शेयरिंग/नॉन शेयरिंग-पैकेज के अनुसार) वॉश एंड चेंज एवं नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था)

कम्फर्ट श्रेणी (2एसी क्लास) में ठहरने पर पैकेज का मूल्य रू०- 56710/- प्रति व्यक्ति एवं प्रति बच्चे (5-11 वर्ष) का पैकेज का मूल्य रू०- 54750/- है। (2एसी क्लास ट्रेन यात्रा, डबल/ट्रिपल पर एसी होटलों में ठहरने, एसी होटल के कमरे में डबल/ट्रिपल पर (शेयरिंग/नॉन शेयरिंग-पैकेज के अनुसार) वॉश एंड चेंज एवं एसी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था).

इस यात्रा सेवा मे LTC एवं EMI की सुविधा भी उपलब्ध है। ईएमआई की सुविधा आईआरसीटीसी पोर्टल पर उपलब्ध सरकारी एवं गैर सरकारी बैंक से ली जा सकती है। इस पैकेज की बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जायेगी। उक्त यात्रा की

बुकिंग हेतु पर्यटन भवन, गोमती नगर, लखनऊ स्थित आईआरसीटीसी कार्यालय एवं आईआरसीटीसी की बेवसाइट www.irctctourism.com से आनलाइन बुकिंग भी कराई जा सकती है।

इस यात्रा के मुख्य आर्कषण निम्नवत हैं:

- यात्रा गंतव्य- तिरुपति बालाजी मंदिर (तिरुपति), रामनाथ स्वामी मंदिर (रामेश्वरम), मीनाक्षी मंदिर (मदुरै), स्थानीय दर्शन (कन्याकुमारी) मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग (मरकापुर),
- श्रेणी अनुसार कुल बर्थो की सं० 751- 02 एसी (कुल 49 सीटें), 03 एसी (कुल 210 सीटें)एवं स्लीपर (कुल 492 सीटें)
- उतरने/चढने के स्टेशन- गोरखपुर - मनकापुर - अयोध्या कैंट सुल्तानपुर - माँ बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ - प्रयागराज संगम - रायबरेली - लखनऊ - कानपुर सेंट्रल उरई - वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी ललितपुर.
- यात्रा तिथि- दिनांक 11-04-2026 से 22-04-2026 तक 11 रात एवं 12 दिन
- सुविधायें- इस पैकेज में 02 एसी, 03 एसी एवं स्लीपर क्लास यात्रा, नाश्ता एवं दोपहर व रात्रि का शाकाहारी भोजन, एसी/ नॉन एसी बसों द्वारा स्थानीय भ्रमण सम्मिलित है।

अधिक जानकारी एवं बुकिंग के लिये नीचे दिये गये मोबाइल नम्बरों पर सम्पर्क कर सकते है: 9236391908, 9305110962, 8287930908, 9415042930, 8287930913, 9236391925

हाईवे और रेलवे परियोजनाओं में आरओबी के लिए अनुमोदन प्रक्रियाओं को डिजिटाइज और तेज करने हेतु PRISM-SG पोर्टल लॉंच

सूत्र/रे.स.ब्यू - बुनियादी ढांचा विकास में दक्षता, पारदर्शिता और अंतर-एजेंसी समन्वय को बढ़ाने की दिशा में एक प्रमुख कदम के रूप में, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी तथा रेलवे, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में PRISM-SG (पोर्टल फॉर रेल-रोड इंस्पेक्शन एंड स्टेजेस मैनेजमेंट स्टील गर्डर्स) पोर्टल लॉन्च किया। PRISM-SG पोर्टल का विकास सड़क ऊपरी पुलों (आरओबी) के निर्माण से संबंधित प्रमुख अनुमोदन और निरीक्षण प्रक्रियाओं को डिजिटाइज करने के लिए किया गया है, जिसमें क्वालिटी एश्योरेंस प्लान (क्यूएपी), वेल्डिंग प्रक्रिया विनिर्देश पत्रक (डब्ल्यूपीएसएस) और स्टील गर्डर्स के निर्माण चरण निरीक्षण को शामिल किया गया है।

यह पोर्टल दस्तावेजों की अंत-से-अंत ऑनलाइन जमा, जांच, प्रश्न उठाना और उनका समाधान, अनुमोदन, निरीक्षण शेड्यूलिंग तथा निरीक्षण रिपोर्ट, फोटोग्राफ, परीक्षण परिणामों की अपलोडिंग को सक्षम बनाता है, जो पूर्ण ऑडिट ट्रेल और वास्तविक समय निगरानी क्षमताओं द्वारा समर्थित है। वर्तमान में, आरओबी के निर्माण के लिए भारतीय रेलवे से जनरल अरेंजमेंट ड्रॉइंग (जीएडी), संरचनात्मक चित्र, क्वालिटी एश्योरेंस प्लान (क्यूएपी), वेल्डिंग प्रक्रिया विनिर्देश पत्रक (डब्ल्यूपीएसएस) और स्टील गर्डर्स के निर्माण चरण निरीक्षण जैसी कई अनुमोदनों की आवश्यकता होती है। जबकि जीएडी और संरचनात्मक चित्रों के अनुमोदन आरआरसीएएस पोर्टल के माध्यम से प्रोसेस किए जाते हैं और क्यूएपी, डब्ल्यूपीएसएस और निर्माण निरीक्षण संबंधी प्रक्रियाएं मुख्य रूप से ऑफलाइन या भौतिक मोड में की जाती हैं। इससे अक्सर विलंब होता है साथ ही हितधारकों के बीच वास्तविक समय ट्रैकिंग और समन्वय सीमित रहता है।

नव लॉन्च PRISM-SG पोर्टल इन चुनौतियों का समाधान करता है, जो सड़क स्वामित्व विभागों, भारतीय रेलवे, ठेकेदारों, फैब्रिकेटरों और निरीक्षण एजेंसियों सहित सभी प्रमुख हितधारकों को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। यह पहल अनुमोदन और निरीक्षण समयसीमा को लगभग 12 महीनों से घटाकर 3 से 4 महीनों तक करने में मदद करेगी, जिससे परियोजना दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार होगा। यह आरओबी और रेलवे पुलों के समय पर पूर्ण होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे देश भर में कनेक्टिविटी को मजबूत किया जाएगा और बुनियादी ढांचा वितरण में तेजी आएगी।

भारतीय रेल ने वर्ष 2021 - 2025 के दौरान 52,000 से अधिक गिरफ्तारियाँ और 50,000 से अधिक अपराधियों के खिलाफ अदालतों में मामले दर्ज कर यात्री सुरक्षा और संरक्षा को मजबूती प्रदान की

पिछले 5 वर्षों में शरारती तत्वों की गतिविधियों के कारण ट्रेन के पटरी से उतरने की केवल तीन घटनाएँ दर्ज की गई

सूत्र/रे.स.ब्यू - रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा का दायित्व रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) को सौंपा गया है। आरपीएफ को चोरी, बेईमानी से गबन, उकसावे, मिलीभगत और साजिश जैसे अपराधों में रेलवे संपत्ति (अनाधिकृत कब्जा) अधिनियम, 1966 के प्रावधानों के तहत मामले दर्ज करने का अधिकार प्राप्त है। अपराधी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है और जांच की जाती है, जिसके बाद सक्षम न्यायालय अर्थात विशेष रेलवे मजिस्ट्रेट की अदालत में, तथा कुछ राज्यों में, जहां विशेष रेलवे न्यायालय स्थापित नहीं हैं, वहां जिला न्यायालयों में शिकायत दर्ज की जाती है।

रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी कि पिछले पाँच वर्षों (2021–2025) के दौरान आर. पी. (यू.पी.) अधिनियम, 1966 के प्रावधानों के तहत कुल 52,494 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 50,432 आरोपियों के खिलाफ संबंधित न्यायालयों में शिकायतें दर्ज की गईं।

पिछले पाँच वर्षों (2021–2025) के दौरान पत्थरबाजी की कुल 12,157 घटनाएँ दर्ज की गईं, जिनमें आरपीएफ/जीआरपी द्वारा 8,441 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

पिछले पाँच वर्षों (2021–2025) के दौरान भारतीय रेल में शरारती तत्वों की गतिविधियों के कारण ट्रेन के पटरी से उतरने की केवल तीन घटनाएँ हुईं। पूर्वी तट रेलवे के वाल्टेयर मंडल, उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल और दक्षिण रेलवे के चेन्नई मंडल में ट्रेन के पटरी से उतरने की एक-एक घटना हुई।

रेलवे द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:-

- रेलवे की राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति (एसएलएससीआर) की नियमित बैठकें आयोजित की जा रही हैं। ये समितियाँ प्रत्येक राज्य में संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) या पुलिस आयुक्त की अध्यक्षता में गठित की गई हैं, जिनमें आरपीएफ, जीआरपी और खुफिया इकाइयों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त, तोड़फोड़ की घटनाओं पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए अपराधों पर नियंत्रण, मामले दर्ज करने, उनकी जांच और ट्रेनों का सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए तथा खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान हेतु, आरपीएफ द्वारा राज्य पुलिस/जीआरपी प्राधिकरणों के साथ सभी स्तरों पर घनिष्ठ समन्वय बनाए रखा जाता है।
- केंद्रीय एवं राज्य खुफिया एजेंसियों के अलावा, आरपीएफ की खुफिया इकाइयाँ, अर्थात अपराध खुफिया शाखा (सीआईबी) और विशेष खुफिया शाखा (एसआईबी) को तैनात किया गया है ताकि खुफिया जानकारी एकत्र की जा सके और संबंधित प्राधिकरणों के साथ समन्वय कर किसी भी आपराधिक गतिविधि की पहचान और रोकथाम के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
- रेलवे, आरपीएफ, जीआरपी एवं सिविल पुलिस द्वारा चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स और संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित रूप से गश्त की जा रही है।
- रेलवे की पटरियों के पास पड़े ढीले और बिखरे हुए सामान हटाने के लिए नियमित अभियान चलाए जाते हैं, जिनका उपयोग शरारती तत्व पटरियों पर अवरोध पैदा करने के लिए कर सकते हैं।
- रेलवे की पटरियों के आसपास रहने वाले लोगों को पटरियों पर बाहरी वस्तुएँ रखने, रेल के पुर्जे हटाने, रील बनाने आदि के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया जा रहा है तथा उनसे सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने का अनुरोध किया जाता है।
- निगरानी के लिए ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है तथा सौर ऊर्जा से संचालित स्टैंड-अलोन सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं।

भारतीय रेलवे ने 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' के तहत पांच नए सुधारों की घोषणा की, माल ढुलाई, निर्माण और यात्री सुविधा पर विशेष ध्यान दिया गया

सूत्र/रे.स.ब्यू - रेलवे, सूचना एवं प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि भारतीय रेलवे द्वारा 2026 के दौरान सुधार करने के संकल्प के अनुरूप पांच नए सुधारों को मंजूरी दी गई है। इन नए सुधारों की मंजूरी के साथ, वर्ष 2026 के लिए सुधारों की कुल संख्या नौ हो गई है। श्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि चल रही "सुधार एक्सप्रेस" पहल के तहत, चार सुधारों की घोषणा पहले ही की जा चुकी है और पांच नए सुधार लागू किए जा रहे हैं। इन पांच नए सुधारों में से दो माल ढुलाई से, एक निर्माण से और दो यात्री सुविधा से संबंधित हैं। परिवर्तित करना और नए समाधान पेश करना शामिल था। हालांकि, आगे के परामर्शों से पता चला कि मुख्य समस्या ऑटोमोबाइल वाहक वैगनों के डिजाइन में निहित है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैगन डिजाइन या तो सिंगल-स्टैक या डबल-स्टैक कॉन्फिगरेशन के लिए उपयुक्त हैं, जिससे लचीलापन सीमित हो जाता है। उन्होंने आगे कहा कि कई मार्गों पर सुरंगों और पुलों के कारण प्रतिबंध हैं, जहां आयाम अनुसूची (एसओडी) के प्रतिबंध कुछ प्रकार के वैगनों की आवाजाही को रोकते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए, श्री वैष्णव ने कहा कि रेलवे ने एक सुधार लागू किया है जो विशेष वैगन डिजाइन की अनुमति देता है और साथ ही उद्योग को लचीलापन भी प्रदान करता है। निर्माता अब विशिष्ट मूल-गंतव्य मार्गों के आधार पर उच्च क्षमता वाले वैगन डिजाइन कर सकते हैं।

पहले के थोक सीमेंट नीति सुधार के प्रभाव का उल्लेख करते हुए, उन्होंने कहा कि लागू किए गए परिवर्तनों से लोडिंग में तत्काल वृद्धि हुई - रेल द्वारा परिवहन किए गए थोक सीमेंट का टन भार सितंबर 2025 में लगभग 37,000 टन से बढ़कर जनवरी 2026 तक लगभग 95,000 टन हो गया। उन्होंने इसी तरह की उम्मीद जताई कि नमक और ऑटोमोबाइल परिवहन में सुधार से इन क्षेत्रों में रेल माल ढुलाई की हिस्सेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

निर्माण की गुणवत्ता में सुधार

श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अगला सुधार रेलवे परियोजनाओं में निर्माण की गुणवत्ता में सुधार पर केंद्रित है, जिसमें सात प्रमुख बदलाव शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पहला बदलाव पात्रता मानदंडों से संबंधित है। किसी एक परियोजना के माध्यम से ठेकेदार की क्षमता का आकलन करने की सीमा परियोजना मूल्य के 35 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी गई है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि केवल वही कंपनियां, जिनके पास बड़ी परियोजनाओं को पूरा करने की सिद्ध क्षमता है, समान कार्यों के लिए बोली लगा सकें। इसके अतिरिक्त, पूर्व अनुभव का कम से कम 20 प्रतिशत रेलवे से संबंधित कार्यों में होना अनिवार्य है, यह मानते हुए कि राजमार्ग, बंदरगाह और हवाई अड्डे जैसे विभिन्न क्षेत्रों की जटिलताएं अलग-अलग होती हैं। रेलवे कार्यों के भीतर, जटिलता के स्तर परिभाषित किए गए हैं, जिसमें सिग्नलिंग सबसे जटिल है, इसके बाद ओवरहेड इलेक्ट्रिकल और ट्रैक कार्य आते हैं और तदनुसार प्रासंगिक अनुभव की आवश्यकता होगी। दूसरे बदलाव के तहत बोली सुरक्षा राशि परियोजना मूल्य के 2 प्रतिशत पर निर्धारित की गई है। इसका उद्देश्य तुच्छ बोलियों को हतोत्साहित करना और यह सुनिश्चित करना है कि केवल गंभीर प्रतिभागी ही निविदा प्रक्रिया में शामिल हों। तीसरे बदलाव के तहत 10 करोड़ रुपये से अधिक की सभी परियोजनाओं के लिए बोली क्षमता का अनिवार्य मूल्यांकन किया गया है, जबकि चौथे बदलाव के तहत भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं पर रोक लगाने के लिए सख्त दंडात्मक प्रावधान लागू किए गए हैं। पांचवें बदलाव के तहत किसी भी परियोजना के प्रारंभ से पहले एक विस्तृत कार्य योजना अनिवार्य की गई है, जिससे बेहतर निगरानी संभव हो सकेगी और समय पर निष्पादन सुनिश्चित होगा। छठे बदलाव के तहत अनुमत उप-अनुबंध की सीमा 70 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत कर दी गई है। ठेकेदारों को अब कम से कम 60 प्रतिशत कार्य अपने स्वयं के पर्यवेक्षण में स्वयं निष्पादित करना होगा, जिससे जवाबदेही सुनिश्चित होगी और बोलियां प्राप्त करने के बाद अनुबंधों को हस्तांतरित करने की प्रथा में कमी आएगी। सातवां बदलाव अनुचित बोली प्रक्रिया को संबोधित करता है। उन्होंने कहा कि यदि कोई बोली अनुमानित परियोजना लागत से 5 प्रतिशत से अधिक कम है, तो बोलीदाता को अतिरिक्त 5 प्रतिशत प्रदर्शन गारंटी प्रदान करनी होगी। इसका उद्देश्य उन अवास्तविक बोलियों को हतोत्साहित करना है जो बाद में विवादों, मध्यस्थता और परियोजना में देरी का कारण बनती हैं।

ये बदलाव सामूहिक रूप से रेलवे परियोजना निष्पादन ढांचे को मजबूत बनाते हैं। इनमें सख्त नैतिक और दंडात्मक उपायों के माध्यम से पारदर्शिता और ईमानदारी को बढ़ावा देना, सख्त पात्रता मानदंडों और उप-अनुबंधों में कमी के माध्यम से गुणवत्ता आश्वासन सुनिश्चित करना और निश्चित बोली सुरक्षा, बोली क्षमता मूल्यांकन और अतिरिक्त प्रदर्शन गारंटी जैसे तंत्रों के साथ समय पर डिलीवरी को बढ़ावा देना शामिल है। इन सभी कदमों का उद्देश्य एक अधिक जवाबदेह, कुशल और मजबूत अवसंरचना विकास प्रणाली का निर्माण करना है।

टिकट रद्द करना और धनवापसी

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आठवें सुधार का मुख्य उद्देश्य यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करना है, जिसमें टिकट प्रणाली के दुरुपयोग को रोकने और वास्तविक यात्रियों की पहुंच में सुधार लाने के उपाय शामिल हैं। उन्होंने कहा कि टिकटों की कालाबाजारी और तत्काल प्रणाली का दुरुपयोग एक बड़ी चिंता का विषय रहा है। इससे निपटने के लिए, रेलवे ने बॉट्स और फर्जी सॉफ्टवेयर का पता लगाने के लिए तकनीक पेश की। इसके अलावा, तकनीकी हस्तक्षेपों से एजेंटों और दलालों द्वारा तत्काल विंडो खुलने के तुरंत बाद टिकट बुक करने की क्षमता पर अंकुश लगाया गया, साथ ही आधार-आधारित ओटीपी सत्यापन भी शुरू किया गया। विस्तृत डेटा विश्लेषण से IRCTC प्रणाली से लगभग 3 करोड़ फर्जी खातों की पहचान और उन्हें हटाने में सफलता मिली, जिसके परिणामस्वरूप टिकटों की उपलब्धता में उल्लेखनीय सुधार हुआ।

इस समस्या के समाधान के लिए, प्रस्थान से पहले 48, 12 और 4 घंटे की पूर्व रद्द करने की समय सीमा को संशोधित करके 72, 24 और 8 घंटे कर दिया गया है, जो आरक्षण चार्ट की अग्रिम तैयारी के अनुरूप है, जो अब प्रस्थान से 4 घंटे के बजाय 9-18 घंटे पहले तैयार किया जाता है। यह यात्रियों के लिए निःशुल्क होगा। अग्रिम आरक्षण चार्ट अनिश्चितता को कम करके, प्रतीक्षा सूची में शामिल यात्रियों के लिए बेहतर योजना बनाने में सहायता करके और दूरस्थ स्थानों से आने वाले यात्रियों को सहयोग प्रदान करके यात्रियों की सुविधा को बढ़ाता है। समय रहते बुकिंग करने से वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था संभव होती है, खाली बर्थों का अधिकतम उपयोग होता है और पारदर्शिता बढ़ती है। इन परिवर्तनों का उद्देश्य अंतिम समय में होने वाली अटकलबाजी वाली बुकिंग को हतोत्साहित करना और यह सुनिश्चित करना है कि टिकट केवल वास्तविक यात्रियों को ही उपलब्ध हों। केंद्रीय मंत्री ने यह भी घोषणा की कि अब जल्द ही देश भर के किसी भी रेलवे स्टेशन से काउंटर टिकट रद्द किए जा सकेंगे, जिससे पहले की वह पाबंदी हट जाएगी जिसके तहत टिकट केवल प्रस्थान स्टेशन पर ही रद्द किए जा सकते थे। उन्होंने कहा कि ई-टिकटों के लिए टिकट जमा रसीद (टीडीआर) दाखिल करने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है और रद्द करने पर रिफंड स्वतः ही संसाधित हो जाएगा। यात्रियों के लिए एक अन्य उपाय के तहत, यात्री अब प्रस्थान से 30 मिनट पहले तक अपनी यात्रा श्रेणी को अपग्रेड कर सकते हैं, जबकि पहले यह बदलाव चार्ट तैयार होने से पहले ही संभव था। उन्होंने कहा कि इन सुधारों से पारदर्शिता में और सुधार होने, दुरुपयोग कम होने और रेलवे टिकटिंग में यात्री अनुभव बेहतर होने की उम्मीद है।

ट्रेन बोर्डिंग पॉइंट में बदलाव

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सुधार संख्या नौ से यात्रियों को ट्रेन के प्रस्थान स्टेशन से 30 मिनट पहले तक डिजिटल रूप से अपना बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा मिलती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पहले यात्री केवल चार्ट तैयार होने से पहले ही बोर्डिंग पॉइंट बदल सकते थे। नए प्रावधान के तहत, यदि कोई यात्री अपने मूल स्टेशन से ट्रेन में चढ़ने में असमर्थ है, तो वे अगले सुविधाजनक स्टेशन का चयन कर सकते हैं और अपनी पुष्ट सीट खोए बिना ट्रेन में चढ़ सकते हैं।

पूर्व सुधारों पर अद्यतन जानकारी

पूर्व सुधारों में बेहतर ऑन-बोर्ड सेवाओं के लिए सुधार, माल ढुलाई लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बेहतर सुविधाओं से युक्त गति शक्ति कार्गो टर्मिनलों का विस्तार, रेलटेक नीति और पोर्टल, और त्वरित, कागजी निपटान के लिए रेलवे दावा न्यायाधिकरण (ई-आरसीटी) का डिजिटलीकरण शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सामान्य और अनारक्षित डिब्बों के लिए ऑन-बोर्ड सफाई सेवाओं को एक मिशन के रूप में लिया गया है। सभी क्षेत्रीय रेलवे में कुल 86 ट्रेनों की पहचान की गई है। 5 क्षेत्रीय रेलवे द्वारा पैनल में शामिल होने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति पहले ही जारी की जा चुकी है। माल ढुलाई सुधारों पर उन्होंने कहा कि गति शक्ति कार्गो टर्मिनल नीति में बदलाव अधिसूचित कर दिए गए हैं और संशोधित ढांचे के तहत नए आवेदनों पर कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में शुरू की गई रेल टेक नीति का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एक महीने के भीतर 123 प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से 94 को अगले चरण के लिए चुना गया है।

Indian railways sanction historic Talwandi Sabo rail link to Takht Sri Damdama Sahib, now joining all the five takhts

Source/RSB- A historic milestone has been achieved with the sanctioning of the railway link to Talwandi Sabo, the sacred land of Takht Sri Damdama Sahib-one of the five Takhts of Sikhism. Sharing this moment with pride, Union Minister of State for Railways & Food Processing Industries, S. Ravneet Singh, announced in Bathinda that this project is not merely about building a railway line—it represents faith, pride, and long-overdue justice for Punjab. With this development, Takht Sri Damdama Sahib will now be connected by rail to the other four Takhts, marking a significant step in strengthening religious and regional connectivity.

The Raman Mandi–Sadda Singhwala New Broad Gauge Rail Line Project is a major infrastructure initiative under the Mansa–Bathinda Doubling Project. Spanning 42.9 km, the project will cost ₹1118.47 crore, with an average cost of ₹26.07 crore per kilometer. It will cover the districts of Mansa and Bathinda and is expected to significantly enhance transportation and regional development.The project requires 192.42 hectares of land, including 40.508 hectares in Mansa district and 151.912 hectares in Bathinda district. It will include six stations—two existing and four new ones: Laleana, Talwandi Sabo, Jaga Ram Tirath, Kamalu Sawaich, along with a junction cabin at Kamalu Sawaich.

Designed as a completely level crossing-free rail link, the project will feature two major bridges, one additional major bridge component, 56 minor bridges, and 55 road under bridges (RUBs). It will also be equipped with 2x25 KV electric traction and the advanced MACLS-III signaling system. Speaking on the occasion, Ravneet Singh questioned the past governments in Punjab, stating that despite decades of rule by Congress, followed by AAP and the Shiromani Akali Dal, meaningful infrastructure development and respect for Sikh heritage were neglected. He emphasized that while these parties used faith and emotions for political gain, they failed to deliver concrete results—such as connecting all five Takhts by rail.

He concluded by thanking the current leadership under Prime Minister Narendra Modi for taking tangible steps to honor Sikh faith through development and infrastructure, finally addressing long-pending demands of the people.

WR commissions Gati Shakti Cargo Terminal at Gangadhra

Source/RSB- Western Railway has operationalized a new Gati Shakti Cargo Terminal at Gangadhra, marking a significant advancement in regional freight infrastructure. The terminal was commissioned by Shri Pradeep Kumar, General Manager of Western Railway, who also flagged off the first container train from the facility, signaling the start of operations.

Spread across more than 44,000 square meters and developed entirely on Western Railway land, the terminal is designed to enhance logistics efficiency, particularly for Surat's key cement and textile industries. The facility is expected to streamline cargo handling and improve supply chain performance in the region.

By shifting a substantial portion of freight movement from road to rail, the project is set to reduce road congestion and lower environmental impact. Additionally, the diversion of heavy cargo to rail networks is expected to free up track capacity for faster and more efficient passenger train operations, contributing to an overall improvement in railway service delivery.

RITES Honoured at National Mobility Awards 2026 for Excellence in Integrated Mobility

RITES Ltd has been honoured at the National Mobility Awards 2026 in the Metro, Rail and Multimodal Integration category. The recognition highlights the organisation's continued focus on delivering integrated mobility solutions across transport sectors.

The award acknowledges RITES Ltd's contribution towards developing future-ready infrastructure and promoting seamless connectivity through multimodal integration. It reflects the company's commitment to innovation, efficiency, and excellence in supporting India's evolving transportation ecosystem.

Gati Shakti Vishwavidyalaya & DGCA Sign MoU to Revamp Aircraft Maintenance & Create Jobs

Source/RSB- A Memorandum of Understanding was signed between Gati Shakti Vishwavidyalaya (GSV), India's leading university for the transportation and logistics sector and Directorate General of Civil Aviation (DGCA) at Rail Bhawan 0n 30th March. This significant MoU was signed by Sh. Faiz Ahmed Kidwai (DG, DGCA) and Prof. Manoj Choudhary (VC, GSV) in the presence of Union Minister for Railways, Information & Broadcasting, and Electronics & Information Technology, Shri Ashwini Vaishnav & Union Civil Aviation Minister Shri K. Ram Mohan Naidu. The Chairman of Railway Board, Sh. Satish Kumar and the Union Secretary of Civil Aviation, Sh. Samir Kumar Sinha were present amongst other top officials of Railways and Civil Aviation.

This strategic collaboration aims to support and enable the fast-growing Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) sector in India by strengthening human capital and revamping Aircraft Maintenance Engineering (AME) training. The partnership will focus on standardizing AME education, enhancing quality benchmarks, and making MRO careers more aspirational for the youth through the introduction of an undergraduate degree in Aviation Maintenance Engineering.

Speaking at the event, Sh. Ashwini Vaishnaw suggested establishing a Centre of Excellence at Gati Shakti Vishwavidyalaya focused on manufacturing technologies, particularly those requiring high levels of precision such as in aviation, railways, and marine sectors. The training required in these domains demands a different level of technical accuracy and expertise. Industry-oriented courses play a crucial role in ensuring that students are job-ready upon graduation, with access to diverse employment opportunities.

He further emphasized that global benchmark standards should be followed to guide the development of such programs. Highlighting the potential impact, he noted that at least 1,000 students could benefit annually from such initiatives, and assured that adequate funding support would be arranged to realize this vision.

Sh. Ram Mohan Naidu in his address said, "India's aviation sector is the most progressive sector in the country today, growing at over 10–12% annually, a pace that is expected to continue for the next 15 years. The recent expansion in operational airports, passengers, and aircraft in the national fleet underscores the need to develop a workforce that meets global standards and supports the sector's evolving needs. He highlighted that the recent inauguration of Jewar Airport reflects the scale and pace of development, aligned with the vision of establishing seamless multimodal connectivity across highways, railways, ports, and airports."

He further noted that Gati Shakti Vishwavidyalaya embodies this integrated approach by bringing together diverse logistics sectors that have traditionally functioned in silos. Emphasizing the broader scope of aviation, he underlined that the sector today extends beyond passenger travel to include MRO, skilling and training, and indigenous aircraft component manufacturing, contributing to the vision of Atmanirbhar Bharat. He added that the MoU will help in creating the right talent pool, which, along with proper funding under initiatives like the Udaan scheme, is crucial for sustaining growth and ensuring a skilled workforce for the future.

GSV has already established formal collaborations with leading global and national aviation players including Airbus, Safran, and GMR School of Aviation. The university is also in the process of finalizing partnerships with ENAC France and Hindustan Aeronautics Limited. These collaborations have contributed significantly to the development of a robust, industry-relevant academic curriculum.

Under the MoU, GSV and DGCA will jointly design a future-ready three-year B.Sc. (AME) program that integrates academic rigor, regulatory compliance, and industry-aligned competencies. The program aims to create a highly skilled workforce equipped to meet the evolving demands of India's aviation sector.

The pilot phase of the program will commence in the academic year 2026–27 at a select group of premier AME institutions, including GMR School of Aviation and Air India AME Academy. This phase will serve as a model for academic and regulatory excellence before a structured nationwide rollout.

Sh. Ashwini Vaishnaw Calls for Setting up of a Centre of Excellence for Manufacturing Technologies at GSV, which will Benefit 1,000 Students Every Year

As part of its role as a nodal centre, GSV will collaborate with DGCA as a research partner in emerging areas such as Sustainable Aviation Fuels (SAF) and related domains. The university will also conduct specialized training programs to support the capacity building and upskilling of DGCA personnel.

The partnership establishes a structured bridge between regulation, academia, and industry. While DGCA will continue to define licensing standards under CAR-66 and CAR-147 frameworks, GSV will function as a national academic anchor for curriculum innovation, faculty development, research integration, and industry-linked apprenticeship models.

This scalable and replicable framework aligns with India's vision of reducing dependence on foreign MRO facilities and building strong indigenous maintenance capabilities. By embedding hands-on MRO training, simulation-based learning, OEM partnerships, and competency-driven pathways into AME education, the collaboration is expected to create a future-ready workforce capable of supporting India's expanding airline fleet & enhancing the country's position as a competitive global MRO destination.

Gati Shakti Vishwavidyalaya (GSV), India's only University in Transportation and Logistics sector, was established as a Central University by the Act of Parliament in 2022. Following demand-driven curriculum, the University is mandated to cover the entire transportation sector including Railways, Aviation, Highways, Ports, Maritime, Shipping, Inland Waterways, Urban Transport and complete Logistics and supply chain networks. The university is headed by Sh. Ashwini Vaishnaw (Union Minister for Railways, Information and Broadcasting, Electronics and Information Technology) as the University Chancellor.

IRFC Signs ₹12,842 Crore Loan Agreement with HURL in Major Refinancing Deal

Source/IRFC- Indian Railway Finance Corporation (IRFC) has entered into a significant Rupee Term Loan agreement worth ₹12,842 crore with Hindustan Urvarak and Rasayan Limited (HURL), marking one of its largest refinancing transactions to date.The agreement is part of IRFC's strategic shift under its "IRFC 2.0" initiative, which focuses on expanding its role beyond traditional railway financing to become a diversified infrastructure financier. Through this transaction, IRFC aims to provide cost-effective, long-term capital to sectors connected with the railway ecosystem.The refinancing deal is expected to enhance HURL's financial flexibility by aligning its cash flows more efficiently and reducing financial stress. It will also support the company's operations in the fertilizer sector, contributing to India's broader agricultural framework.

Titagarh Rail Bags Rs. 226.35 Crore Wagon Supply Order from JSW Port Logistics

Source/RSB- Titagarh Rail Systems Limited has secured a significant contract valued at Rs. 226.35 crore from JSW Port Logistics Private Limited for the manufacture and supply of 720 wagons. The wagons will be produced as per mutually agreed technical specifications, tailored to meet the operational requirements of the client.This order reflects the increasing demand for rail-based freight transportation solutions, driven by the need for efficient and scalable logistics infrastructure in India. The contract further strengthens Titagarh Rail Systems Limited's position in the domestic railway manufacturing sector and underscores its growing role in supporting industrial logistics.The deal also highlights continued investment by private sector players such as JSW Port Logistics Private Limited in enhancing cargo movement capabilities through rail, aligning with broader efforts to improve supply chain efficiency and reduce dependence on road transport.

Punjab Mail Train Mahotsav Celebrated at Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus with Enthusiastic Participation

Source/RSB- Punjab Mail Train Mahotsav held at Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus witnessed enthusiastic participation as passengers and rail enthusiasts came together to honour the iconic Punjab Mail. Shri Prateek Goswami, General Manager, Central Railway, Shri Hiresh Mina, Divisional Railway Manager, Mumbai Division, Shri Subodh Kumar Sagar, Principal Chief Mechanical Engineer, along with Principal Heads of Departments, senior officers and staff from Headquarters and Mumbai Division, media persons, rail enthusiasts & passengers were present on the occasion.

Special Awareness Program on Anti-Human Trafficking Organized Under the Joint Aegis of Railway Protection Force, North Central Railway, and National Commission for Women

Source/RSB- With the objective of ensuring the safety of women and children and effectively curbing severe crimes like human trafficking, a special awareness program was successfully organized on March 31, 2026, at Hotel Jaswant Vilas in Mundera, Prayagraj. This event was organized through the joint efforts of the National Commission for Women (NCW) and the Railway Protection Force (RPF), North Central Railway.

Several dignitaries and senior officials participated in this significant event. The prominent attendees included Ms. Babita Chauhan, Chairperson of the State Women Commission (SWC); Dr. Sarfaraz Ahmed Khan, Professor; Mr. Ajit Singh, Representative of Guria NGO; Mr. Rajneesh Agarwal, Divisional Railway Manager, Prayagraj; Mr. Pradeep Kumar Gupta, Principal Chief Security Commissioner of North Central Railway; along with the Chief Security Commissioner and the Senior Divisional Security Commissioner.

During the seminar, experts held detailed discussions on crucial aspects related to the identification of human trafficking, preventive measures, and the rescue and rehabilitation of victims. The speakers strongly emphasized that since traffickers frequently use public transport networks, maintaining vigilant surveillance of any suspicious activities inside railway stations and trains is absolutely essential.

To make this awareness campaign effective at the grassroots level, all sections of railway personnel who come into direct contact with passengers were included. The program witnessed the attendance of 160 RPF personnel, 24 GRP personnel, 25 Commercial Department staff members, 10 vendors, 8 porters, and 3 police personnel.

The primary objective of this program was to sensitize and raise awareness among all agencies and frontline workers, such as vendors, porters, and ticket-checking staff operating within railway premises, regarding incidents of human trafficking. Furthermore, a major goal of this initiative is to strengthen mutual coordination among various security agencies and railway departments to prevent this heinous crime.

Banaras Locomotive Works Creates New History: Record Production of 572 Locomotives — Highest Ever Annual Output

Source/BLW- Banaras Locomotive Works (BLW) has added a new golden chapter to the industrial history of Indian Railways by achieving a record-breaking production of 572 locomotives in the financial year 2025–26 under the capable leadership of General Manager Shri Ashutosh Pant. This milestone stands as strong evidence of BLW's technical excellence, efficient management, and the relentless efforts of its officers and employees.In comparison, 477 locomotives were produced in the previous financial year (2024–25), marking an impressive ~20% increase in production this year. This achievement is a matter of pride not only for BLW but for the entire Indian Railways family.

Breakdown of 572 Locomotives Produced:558 modern electric locomotives for Indian Railways, including:

- WAG-9 – 401 • WAP-7 – 143
- Amrit Bharat Locomotives – 14
- 10 diesel locomotives for export to Mozambique
- 04 diesel locomotives for non railways customers

Notably, against a target of 553 electric locomotives for FY 2025–26, BLW successfully produced 558 units, exceeding the target by approximately 1% and 18% more than previous year.

A Glorious Journey: 11,259 Locomotives Built So Far:

Since its inception, BLW has manufactured a total of 11,259 locomotives, including 2,925 electric locomotives. This reflects BLW's significant contribution to the self-reliance and technological advancement of Indian Railways.

Focus on Modern Technology and Crew Comfort:

BLW prioritizes crew safety and comfort in its locomotives. Advanced features include:Waterless urinals, CLI seats, Signal exchange lights, DPWCS, 'Kavach' safety system - Due to these innovations, BLW has been awarded First Prize for Best Locomotive Cab in the Production Unit category.

BLW has been awarded the ISO 22163 Silver Grade Certification under IRIS by the European body UNIFE, for the second consecutive time. This recognition highlights BLW's commitment to quality, reliability, and global standards.Commitment to Energy Conservation and Environmental Protection

BLW continues to work actively toward sustainability:

Rainwater harvesting through ponds and soak pits conserves thousands of liters of water annually.Installed capacity of grid-connected solar power plant: 3874 kWpSolar energy generated in FY 2025–26: 41.76 lakhs units, accounting for ~19.87% of total annual energy consumption Savings from solar energy approximately ₹1.58 crore

Leadership in Promotion of Hindi :

For outstanding promotion of the official language Hindi, BLW has been awarded the "Rail Minister Rajbhasha Shield" by the Railway Board's Rajbhasha Directorate, reflecting its continued commitment to Hindi.

Moving Towards New Targets:

The Ministry of Railways has set an ambitious target of 642 electric locomotives for BLW for the financial year 2026–27.On this historic achievement, General Manager Shri Ashutosh Pant congratulated all officers, employees, women staff, and their families. He stated that this success is the result of the team's hard work, technical expertise, and strong commitment to achieving targets set by the Railway Board. He expressed confidence that BLW will set new benchmarks in the coming financial year as well.

20% Historic Increase Compared to 477 Locomotives Last Year

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट
आकाश की ऊंचाई-स्पष्ट संदेश
विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश
₹11,200 करोड़ की लागत से तीव्र कनेक्टिविटी देने वाले अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट
नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (प्रथम चरण) का
उद्घाटन
नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री
के द्वारा किया गया
उत्तर प्रदेश की उड़ान – पूरे भारत की शान
• भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजनाओं में एक
• सड़क, रेल, मेट्रो और क्षेत्रीय परिवहन प्रणालियों के बीच निर्बाध एकीकरण वाला मल्टी मोडल ट्रांजिट सिस्टम
• 2.5 लाख+ मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाला मल्टी-मोडल कार्गो हब, जिसे लगभग 18 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाया जा सकता है
• राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रवेश द्वार के अनुरूप
• प्रति वर्ष 1.20 करोड़ यात्री क्षमता
• चतुर्थ चरण तक प्रति वर्ष 7 करोड़ तक यात्री वहन क्षमता का विस्तार
• उत्तर प्रदेश की पारंपरिक एवं हवेलियों की थीम पर आधारित साज-सज्जा, वाराणसी एवं हरिद्वार के गंगा घाट की अनुभूति वाली मल्टी लेवल टर्मिनल डिजाइन
• विभिन्न राज्यों के हैंडीक्राफ्ट्स एवं टेक्सटाइल से सौंदर्यीकरण
गरिमामयी उपस्थिति
आनंदीबेन पटेल
राज्यपाल, उत्तर प्रदेश
योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश
किंजरापु राममोहन नायडू
मंत्री, नागर विमानन, भारत सरकार
पंकज चौधरी
राज्य मंत्री, वित्त, भारत सरकार
केशव प्रसाद मौर्य
उप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश
ब्रजेश पाठक
उप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश
बृजेश सिंह
राज्य मंत्री, लोक निर्माण, उत्तर प्रदेश
डॉ. महेश शर्मा
सांसद, गौतम बुद्ध नगर
सुरेंद्र सिंह नागर
सदस्य, राज्य सभा
अमित चौधरी
अध्यक्ष, जिला पंचायत, गौतम बुद्ध नगर
पंकज सिंह
विधायक, नोएडा
तेजपाल सिंह नागर
विधायक, दादरी
धीरेन्द्र सिंह
विधायक, जेवर
संजय कुमार शर्मा
विधायक, अनूपशहर
सुरेन्दर दिलेर
विधायक, खैर
लक्ष्मी राज सिंह
विधायक, सिकंदराबाद
श्रीकान्त शर्मा
विधायक, मथुरा
मीनाक्षी सिंह
विधायक, खुर्जा
राजेश चौधरी
विधायक, मांट
जयवीर सिंह
विधायक, बरौली
नरेन्द्र सिंह भाटी
सदस्य, विधान परिषद
श्रीचंद शर्मा
सदस्य, विधान परिषद
एवं अन्य गणमान्य महानुभाव
दिनांक : 28 मार्च, 2026 | स्थान : जेवर, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश
विकास की गति अपार-डबल इंजन सरकार
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश